



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 938]

नई दिल्ली, बुधस्पर्तिवार, जून 18, 2009/ज्येष्ठ 28, 1931

No. 938]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2009/JYAISTHA 28, 1931

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2009

का.आ. 1506(अ).—असम के युनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) को विधिविरुद्ध घोषित किए जाने के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान होने अथवा न होने के सम्बन्ध में न्याय-निर्णयन के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति सुश्री रेवा खेत्रपाल की अध्यक्षता में गठित अधिकरण को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(1) के अधीन भेजे गए संदर्भ के सम्बन्ध में पारित उनके आदेश को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4(4) के अनुसरण में आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

[सं. 11011/55/2008-एन.ई.-III]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

अधिकरण की रिपोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति सुश्री रेवा खेत्रपाल की अध्यक्षता में गठित विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण की रिपोर्ट

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 की संख्या 37) (जिसे इसमें इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने दिनांक 27-11-2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2746(अ) द्वारा युनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम को 'विधिविरुद्ध संगठन' घोषित किया था।

2. केन्द्र सरकार ने दिनांक 27.11.2008 की अधिसूचना संख्या का0आ0 2746(अ0) में अपनी यह राय व्यक्त की है कि उल्फा :

- (i) असम को आजाद कराने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में ऐसी विभिन्न विधिविरुद्ध एवं हिंसक गतिविधियों में लिप्त है जो भारत की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखण्डता को विघटित करती है।
- (ii) असम को भारत से पृथक करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ अन्य विधिविरुद्ध संगठनों के साथ गठजोड़ कर लिया है।
- (iii) अपने उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उल्फा, विधिविरुद्ध संगठन घोषित होने की अवधि के दौरान, अनेक विधिविरुद्ध एवं हिंसक क्रियाकलापों में शामिल रहा है।
- (iv) सीमा-पार से और अधिक अवैध शस्त्र एवं गोला-बारूद को प्राप्त करने तथा उन्हें लाने में संलिप्त है।
- (v) अपने विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के लिए जनता से भारी मात्रा में जबरन धन वसूली और करों की अवैध वसूली करता है।

3. इसके संविधान पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (जिसे इसमें इसके बाद 'उल्फा' कहा गया है) और इसके विभिन्न गुटों की स्थापना दिनांक 7 अप्रैल 1979 को हुई थी जिसका घोषित उद्देश्य, सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत संघ से "असम को आजाद कराना" था। अपने इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस संगठन ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य सशस्त्र अलगाववादी संगठनों से गठजोड़ किया और इसे, निम्नलिखित गतिविधियों के लिए, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत दिनांक 27 नवम्बर, 1990 को प्रथम बार 'विधिविरुद्ध संगठन' घोषित किया गया था:

- (i) असम को भारत से आजाद कराने का लक्ष्य;

- (ii) भारत की संप्रभुता और अखंडता को विघटित करने और लोगों में असुरक्षा की गहन भावना पैदा करने के उद्देश्य से अनेक प्रकार की अवैध एवं हिंसक गतिविधियों में संलिप्त होना;
- (iii) जबरन धन वसूल करना, राजनीतिक नेताओं, पुलिस अधिकारियों, व्यापारियों एवं अन्य लोगों की हत्या करना;
- (iv) धमकाने, डराने, लोगों का अपहरण करने, लाईसेन्स धारकों से उनके आग्नेयास्त्र छीनने, डकैती डालने, राजमार्गों पर लूटपाट करने और बैंकों को लूटने, भूमि और भवनों को बलपूर्वक हथियाने के कृत्यों में संलिप्त रहना।

4. उल्फा को 'विधिविरुद्ध संगठन' घोषित करने वाली दिनांक 27 नवम्बर, 1990 की अधिसूचना की वैधता में समय-समय पर विस्तार किया गया और इस संगठन को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत 'विधिविरुद्ध संगठन' घोषित करने वाली वर्तमान अधिसूचना की वैधता दिनांक 26 नवम्बर, 2008 तक थी। इस संगठन को उक्त अधिनियम की धारा 35 के तहत एक 'आतंकवादी संगठन' भी घोषित किया गया है।

5. उल्फा, वर्ष 1991 से लेकर दिनांक 15 अक्टूबर, 2008 तक की अवधि के दौरान, 368 पुलिस कार्मिकों सहित 1984 व्यक्तियों की हत्याएं करने के लिए उत्तरदायी है। यह उल्लेख किया गया है कि उल्फा के काडरों ने वर्ष 2008 (15 अक्टूबर, 2008 तक) के दौरान हिंसा की 117 वारदातों में 3 सुरक्षा कार्मिकों सहित 43 व्यक्तियों की हत्याएं की और वर्ष 2007 की इसी अवधि के दौरान यह हिंसा की 201 वारदातों में 7 सुरक्षा कार्मिकों सहित 185 व्यक्तियों की हत्याओं के लिए उत्तरदायी है। पिछले वर्ष की तुलना में, वर्ष 2007 के दौरान, उल्फा द्वारा की गई हिंसक वारदातों में सबसे अधिक, अर्थात् 12.4 प्रतिशत की, और हत्याओं में 83.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। हालिया रिपोर्टें यह दर्शाती हैं कि असम के निचले इलाकों के विभिन्न जिलों में दिनांक 30 अक्टूबर, 2008 को हुए नौ क्रमिक बम विस्फोटों, जिनमें 76 व्यक्ति मारे गए थे और 351 लोग जख्मी हुए थे, में उल्फा का हाथ था, हालांकि उल्फा ने इन बम विस्फोटों में अपना हाथ होने से इन्कार किया है।

6. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में, केन्द्र सरकार की यह राय है कि उल्फा को अधिनियम के तहत अगले दो वर्ष के लिए 'विधिविरुद्ध संगठन' घोषित करना आवश्यक है; और इस संगठन को 'विधिविरुद्ध संगठन' घोषित करने वाली पिछली वैध तिथि की समाप्ति और इस संगठन को 'विधिविरुद्ध संगठन' घोषित करने की नई तारीख के बीच कोई अन्तराल नहीं होना चाहिए क्योंकि किसी भी प्रकार की देरी से इस संगठन को अनापेक्षित लाभ मिल सकता है। अतः, इस संगठन को, दिनांक 27 नवम्बर, 2008 से तत्काल प्रभाव से, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उप-धारा (3) के परन्तुक के तहत 'विधिविरुद्ध संगठन' घोषित करना आवश्यक प्रतीत होता है।

7. अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने, असम के उल्फा नामक संगठन को विधिविरुद्ध संगठन घोषित किए जाने के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान होने अथवा न होने के सम्बन्ध में न्याय-निर्णयन के लिए, दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 की अपनी अनुवर्ती अधिसूचना सं० का०आ० 2943(अ०) के तहत इस अधिकरण का गठन किया और श्री आर० आर० झा, निदेशक (एन०ई० II) द्वारा, अधिनियम की धारा 4(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत, दिनांक 23 दिसम्बर, 2008 के सन्दर्भ संख्या 11011/55/2008-एन०ई० III के तहत इस अधिकरण को मामला प्रस्तुत किया गया।

8. इस अधिकरण में यह मामला दिनांक 23 दिसम्बर, 2008 को प्राप्त हुआ।

9. दिनांक 23 दिसम्बर, 2008 के आदेश के तहत मामला प्राप्त होने पर इस अधिकरण द्वारा प्राथमिक सुनवाई के लिए दिनांक 12 जनवरी 2009 की तारीख निर्धारित की गई।

10. मामले और केन्द्र सरकार द्वारा अभिलेखों में दर्ज सामग्री पर विचार करने के उपरान्त, अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के प्रावधानों के अनुसरण में, इस अधिकरण ने अपने दिनांक 12.01.2009 के आदेश के तहत, सम्बन्धित राज्यों के मुख्य सचिवों के माध्यम से उल्फा को नोटिस भेजा और निदेश दिया कि इस नोटिस की तामील के 30 दिन के भीतर लिखित में कारण बताए जाएं कि उल्फा को विधिविरुद्ध संगठन घोषित क्यों न किया जाए। सन्दर्भित आदेश के माध्यम से अधिकरण

ने यह भी निदेश दिया कि इस नोटिस की तामील, दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों और दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करके, एसोसिएशन के उस पते पर, जहां उल्फा का कार्यालय है या असम राज्य में एवं उसके बाहर, जहां उसकी विद्यमानता विदित है, की जाए और साथ-ही-साथ रेडियो और दूरदर्शन तथा समाचार पत्रों में प्रसारित किया जाए और सन्दर्भित संगठन के किसी संदिग्ध स्थान, यदि कोई हो, पर नोटिस की प्रति चिपकाकर की जाए, और जहां सम्भव हो, इस नोटिस की तामील संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों, यदि कोई हों, को उनके पते पर रजिस्टर्ड डाक अथवा अन्य किसी प्रकार से नोटिस भेज कर की जाए। उन क्षेत्रों, जहां पर सन्दर्भित संगठन द्वारा सामान्यतः अपनी गतिविधियां चलाई जा रही हैं, में नोटिस की विषय-वस्तु की घोषणा, ढोल बजाकर करने के साथ-साथ लाऊडस्पीकरों द्वारा भी की जाए। यह अतिरिक्त निदेश दिया गया कि उस नोटिस को जिला अथवा तहसील मुख्यालय के प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार कार्यालय और उपायुक्त कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर और जहां तक व्यवहार्य हो, बाजार में विभिन्न स्थानों पर चिपकाकर नोटिस की तामील कराई जाए।

11. तामील की स्थिति सुनिश्चित करने और आगे की कार्रवाईयों हेतु मामले की सुनवाई के लिए 27 फरवरी, 2009 की तारीख निर्धारित की गई। इसी बीच, केन्द्र सरकार और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैण्ड की सरकारों को अपने-अपने शपथ-पत्र और उपर्युक्त संगठन को विधिविरुद्ध घोषित करने को वैध ठहराने वाले आधारों के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया।

12. तामील के सम्बन्ध में, श्री आर०आर० झा, निदेशक, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली; श्री एस० के० राय, संयुक्त सचिव, असम सरकार, राजनीतिक (ए) विभाग, असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी; डॉ० श्रीरंजन, आयुक्त एवं सचिव, मेघालय सरकार, राजनीतिक विभाग, शिलांग, मेघालय; श्री अविनाश कुमार मिश्रा, प्रधान स्थानिक आयुक्त, अरुणाचल प्रदेश सरकार और सुश्री खरिनो मेहता, संयुक्त स्थानिक आयुक्त, नागालैण्ड सरकार द्वारा शपथ-पत्र दायर किए गए।

13. श्री आर०आर० झा, निदेशक, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दायर शपथ-पत्र में यह उल्लेख किया गया कि दिनांक 12.01.2009 के आदेश के अनुसरण में असम सरकार और मेघालय सरकार ने नोटिस की प्रभावी तामील के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं।
14. श्री एस० के० राय, संयुक्त सचिव, असम सरकार, राजनीतिक (ए) विभाग, असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2009 को दायर किए गए तामील सम्बन्धी शपथ-पत्र में कहा गया है कि इस अधिकरण द्वारा जारी किए गए नोटिस को स्थानीय हिन्दी समाचार पत्र "प्रातः खबर" में दिनांक 28.01.2009 को और प्रमुख प्रान्तीय असमी समाचार पत्र "दैनिक जन्मभूमि" में दिनांक 13.02.2009 को, "अजीर दैनिक बतोरी" में दिनांक 13.02.2009 को और "अमर असम" में दिनांक 28.01.2009 को प्रकाशित किया गया। शपथ-पत्र के साथ समाचार पत्रों की कतरनें भी संलग्न की गई थीं। यह भी उल्लेख किया गया कि नोटिस को दूरदर्शन केन्द्र से दिनांक 28.01.2009 के सांध्य क्षेत्रीय समाचारों में प्रसारित किया गया एवं दिखाया गया और दूरदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी द्वारा इसकी पुष्टि के सम्बन्ध में जारी किया गया पत्र मूल रूप में शपथ-पत्र के साथ संलग्न किया गया था। यह भी उल्लेख किया गया कि महत्वपूर्ण स्थानों, हाटों और बाजारों में ढोल बजाकर और लाऊडस्पीकर द्वारा नोटिस की घोषणा की गई और नोटिस को जिला मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार के कार्यालय और पुलिस थानों में चिपकाया गया। इसके अतिरिक्त, यह उल्लेख भी किया गया है कि जाने-माने उल्फा कार्यकर्ताओं के परिवार के सदस्यों को निष्पक्ष गवाहों की उपस्थिति में इस नोटिस की तामील करवाई गई। उल्लेख किया गया है कि ऐसी कार्रवाई असम के 23 ऐसे जिलों, नामतः, नोगांव, सोनितपुर, मोरीगाव, गुवाहाटी शहर, गोलपाड़ा, नालबाडी, जोरहाट, धेमजी, दर्रांग, शिवसागर, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, कार्बी, अंगलांग, बोंगाईगांव, कोकराझार, गोलाघाट, बरपेटा, धुबरी, उदलगुड़ी, लखीमपुर, चिरांग, कामरूप और बक्सा में की गई जहां तथाकथित विधिविरुद्ध संगठन (उल्फा) अपनी गतिविधियां चला रहा है। उल्फा से नोटिस की तामील करवाने के सम्बन्ध उपर्युक्त उल्लिखित जिलों के पुलिस अधीक्षकों द्वारा भेजे गए पत्रों की प्रतियां शपथ-पत्र के साथ संलग्न की गई हैं।

15. डॉ० श्रीरंजन, आयुक्त एवं सचिव, मेघालय सरकार, राजनीतिक विभाग, शिलांग, मेघालय द्वारा दायर किए गए तामील सम्बन्धी शपथ-पत्र में कहा गया है कि इस अधिकरण द्वारा दिनांक 12.01.2009 को पारित किए गए आदेश के अनुसरण में, 1967 के अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के तहत उत्फा को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का, मेघालय राज्य के विशेषकर उन जिलों, जहां उत्फा बहुत अधिक सक्रिय है, में इलैक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है। इसके अतिरिक्त यह उल्लेख किया गया है कि इस नोटिस को राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार पत्र, "दि इंडियन एक्सप्रेस", दिनांक 12 फरवरी, 2009 (अनुलग्नक-‘ए-1’) के साथ-साथ, स्थानीय अंग्रेजी समाचार पत्र, "शिलांग टाइम्स", 12 फरवरी, 2009 (अनुलग्नक-‘ए-2’), प्रान्तीय समाचार पत्र, "सालनतिनि जनेरा", दिनांक 12 फरवरी, 2009 (अनुलग्नक-‘ए-3’) और एक अन्य स्थानीय समाचार पत्र, "यू नोगसेन हिमा", 12 फरवरी, 2009 (अनुलग्नक-‘ए-4’) में भी प्रकाशित किया गया था। अधिसूचनाओं/नोटिसों की विषय-वस्तु को ऑल इंडिया रेडियो के शिलांग केन्द्र से दिनांक 12 फरवरी, 2009 को सांयकालीन खासी, गारो एवं जयन्तिया बुलेटिनों पर प्रसारित किया गया और दूरदर्शन केन्द्र शिलांग से दिनांक 11.02.2009 को सांय 6.30 बजे दिखाया गया (अनुलग्नक-‘ए-5’)। इसके अतिरिक्त, यह उल्लेख किया गया है कि अधिसूचनाओं/नोटिसों को, राज्य के पश्चिमी गारो हिल्स जिले, पूर्वी गारो हिल्स जिले और पश्चिमी खासी हिल्स जिले के उपायुक्त कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर भी चिपकाया गया (अनुलग्नक-‘ए-6’)।

16. श्री अविनाश कुमार मिश्रा, प्रधान स्थानिक आयुक्त, अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा भी दिनांक 22 मार्च, 2009 को एक तामील सम्बन्धी शपथ-पत्र दायर किया गया जिसमें उल्लेख किया गया है कि अधिकरण द्वारा दिनांक 12.01.2009 को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार पत्र, "टाइम्स ऑफ इंडिया", गुवाहाटी संस्करण, 03.03.2009 के अंक में, "दि टेलीग्राफ न्यूजपेपर", गुवाहाटी संस्करण, 05.03.2009 के अंक में, "अरुणाचल टाइम्स", दिनांक 07.02.2009 के अंक में और दैनिक समाचार पत्र "अरुणाचल फ्रंट", दिनांक 07.02.2009 के अंक में प्रकाशित कराते हुए इसकी तामील पूरी कर ली गई थी। आगे यह उल्लेख किया गया है कि कारण

बताओ नोटिस का प्रसारण केबल नेटवर्क के सभी स्थानीय चैनलों पर दिनांक 13.02.2009 से 07.03.2009 तक किया गया और स्थानीय केबल नेटवर्क के प्रबन्धक द्वारा इसकी पुष्टि दिनांक 06.03.2009 को की गई थी, ऑल इंडिया रेडियो, इटानगर से इसका प्रसारण अंग्रेजी और हिन्दी में दिनांक 03.03.2009 और 04.03.2009 को सांय 6.00 बजे किया गया और ऑल इंडिया रेडियो, इटानगर के कार्यक्रम कार्यकारी द्वारा इसकी पुष्टि दिनांक 05.03.2009 को की गई थी। इस सम्बन्ध में समाचार का प्रसारण दूरदर्शन केन्द्र के नार्थ-ईस्ट न्यूज पर भी दिनांक 18.02.2009 को सांय 7.15 बजे किया गया था और दूरदर्शन केन्द्र, इटानगर के कार्यालयाध्यक्ष से इसकी पुष्टि की जानकारी दिनांक 19.02.2009 को प्राप्त हुई थी। तिरप जिला, खोंसा के उपायुक्त, ने दिनांक 05.03.2009 को, चेंगलांग जिले के उपायुक्त ने दिनांक 04.03.2009 को, लोहित जिला, तेजू के उपायुक्त ने दिनांक 04.03.2009 को और निचली देबांग घाटी जिले के उपायुक्त ने दिनांक 05.03.2009 को यह पुष्टि की कि अधिसूचना और कारण बताओ नोटिस को पूरे जिले के नोटिस बोर्डों पर चिपका दिया गया है और जिले के सभी परिमंडलों में लोक सूचना प्रणाली के माध्यम से घोषणा कर दी गई है। विभिन्न जिलों के उपायुक्तों ने भी नोटिस की तामील की पुष्टि की।

17. सुश्री खरिनो मेहता, संयुक्त स्थानिक आयुक्त, नागालैण्ड सरकार द्वारा भी दिनांक 26 मार्च, 2009 को इस आशय का एक तामील सम्बन्धी शपथ-पत्र दायर किया गया कि इस अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुसरण में उल्फा को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का इलैक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मीडिया, दोनों पर व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया गया। दैनिक समाचार पत्र "नागालैण्ड पोस्ट", दिनांक 19.03.2009, दैनिक समाचार पत्र "ईस्टर्न मिरर", दिनांक 19.03.2009 और दैनिक समाचार पत्र "मोरुंग एक्सप्रेस", दिनांक 19.03.2009 में प्रकाशित नोटिस युक्त समाचार पत्रों की कतरनें शपथ-पत्र के साथ संलग्न की गई हैं। यह भी उल्लेख किया गया कि नोटिस की विषय-वस्तु को ऑल इंडिया रेडियो के कोहिमा केन्द्र से प्रसारित किया गया था और दूरदर्शन केन्द्र, कोहिमा के माध्यम से टेलीविजन पर दिखाया गया था। नोटिस को, राज्य के विभिन्न जिलों के उपायुक्त कार्यालयों के नोटिस बोर्डों पर भी चिपकाया गया था।

18. उपर्युक्त उल्लिखित तरीके से असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैण्ड राज्यों में उल्फा को भेजे गए नोटिसों की तामील की गई। तथापि, नोटिस की तामील की तारीख से 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर और यहां तक कि उस अवधि के बाद भी उल्फा की ओर से कोई आपत्ति/उत्तर/लिखित बयान दायर नहीं किया गया। उल्फा की ओर से व्यक्तिगत रूप से अथवा वकील के माध्यम से भी कोई पेश नहीं हुआ। तथापि, किसी श्री घनश्याम दास से दिनांक 04.02.2009 का इस आशय का एक हस्ताक्षर रहित पत्र प्राप्त हुआ है कि वह असम के यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) का एक सदस्य था, परन्तु वह दिनांक 01.11.2007 को प्रशासन के सम्मुख मुख्यधारा में लौट आया था और इस दृष्टि से नोटिस में उल्लिखित अधिसूचना पर किसी प्रकार की टिप्पणी करने का हकदार वह नहीं था।

19. असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों ने दस्तावेज समर्थित शपथ-पत्रों द्वारा साक्ष्य दिए हैं।

20. अधिकरण द्वारा, प्रथम बार शिलांग के होटल पाईनवुड में दिनांक 26 एवं 27 अप्रैल को सुनवाई की गई, जिसमें डॉ० श्रीरंजन, आयुक्त एवं सचिव, मेघालय सरकार, राजनीतिक विभाग, शिलांग, ने इस सार्वजनिक नोटिस, कि अधिकरण दिनांक 26 एवं 27 अप्रैल, 2009 को प्रातः 10.30 बजे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों के साक्ष्य को रिकार्ड करेगा, को प्रकाशित कराए जाने के साक्ष्य के रूप में दैनिक समाचार पत्रों, अर्थात् "माफोर", दिनांक 20 अप्रैल, 2009, "दि मेघालय गार्जियन", दिनांक 28 अप्रैल, 2009 और "सलनतिनि जनेरा", तुरा मंगोलबार, दिनांक 21 अप्रैल, 2009 के उद्धरण अभिलेखों पर रखे। डॉ० श्रीरंजन ने, अधिकरण द्वारा की जाने वाली सुनवाई के प्रसारण को समाचार के रूप में अपने समाचार आधारित कार्यक्रम "सिटी स्कैन" में खासी और अंग्रेजी भाषा में दिनांक 18.04.2009 (शनिवार) सांय प्रसारित करने की पुष्टि के सम्बन्ध में प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दूरदर्शन केन्द्र, लठकोर पीक, शिलांग (मेघालय) से प्राप्त पत्रों को अभिलेखों पर रखा।

21. एस0 डब्ल्यू-1, डॉ0 श्रीरजन, जिन्होंने साक्ष्य के रूप में अपना शपथ-पत्र, अनुलग्नक ए-1 से ए-11 प्रदर्श, प्रदर्श के रूप में एस0 डब्ल्यू-1/ए (समेकित रूप से) के साथ प्रस्तुत किया है, के अनुसार, मेघालय में उल्फा के अवैध एवं विधिविरुद्ध क्रियाकलापों की समस्या मुख्य रूप से ईस्ट गारो हिल्स और वेस्ट गारो हिल्स में है। गवाह ने उल्लेख किया है कि उल्फा प्राथमिक रूप से अपहरण, जबरन धन वसूली, फिरौती की मांग करने, अवैध हथियारों एवं गोला-बारूद को अपने कब्जे में रखने और उसका प्रयोग करने तथा निर्दोष लोगों की हत्याएं करने जैसे अवैध और विधिविरुद्ध कृत्यों को अंजाम देता था। उल्फा के सम्बन्ध, बांग्लादेश में अवैध और विधिविरुद्ध गतिविधियां चलाने वाले कुछ गुटों से भी थे; और ईस्ट एवं वेस्ट गारो हिल्स क्षेत्र का प्रयोग, बांग्लादेश से भारत में अवैध अप्रवासन के मार्ग के रूप में किया जाता था। उल्फा के लक्ष्य एवं उद्देश्य राष्ट्र-विरोधी थे क्योंकि वह भारत से अलग होना चाहता है। उनके द्वारा किया जाने वाला दुश्प्रचार यह था कि भारत ने उनके क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर रखा है। निर्दोष लोगों के अतिरिक्त, उल्फा का मुख्य निशाना सशस्त्र सेनाएं और कार्यकारी के सदस्य थे। उनकी गतिविधियां जो पहले कमोबेश रूप से गुप-चुप थीं अब और अधिक खुलकर सामने आ गई हैं। उल्फा के कई काडरों को हथियारों और गोला-बारूद सहित पकड़ा गया है, जैसा कि शपथ-पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नकों, ए-7, ए-8, ए-9 और ए-10 (समेकित रूप से) से प्रकट होता है। उल्फा के कुछ गुटों ने मेघालय सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण भी कर दिया है। दिनांक 28.08.2008 को, कुछ उल्फा काडरों ने, ईस्ट गारो हिल्स जिले के रेसुबेलपाड़ा स्थित भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबन्धक श्री सुरजा कुमार गोगोई को एक मांग नोटिस भेजा जिसमें 5,00,000/-रूपये (पांच लाख रुपये कुल) की मांग की गई थी। सन्दर्भित मांग नोटिस को शपथ-पत्र के साथ अनुलग्नक ए-11 के रूप में संलग्न किया गया है। गवाह के अनुसार, उल्फा के सम्बन्ध, लिब्रेशन ऑफ एचिक इलाइट फोर्स (एल0ए0ई0एफ0) और पीपुल्स लिब्रेशन फ्रंट (पी0एल0एफ0) जैसे अन्य उग्रवादी संगठनों के साथ भी हैं। उनकी अवैध गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक था क्योंकि अब वे ईस्ट एवं वेस्ट गारो हिल्स क्षेत्र में खुलेआम अपनी गतिविधियां चला रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि उनकी गतिविधियों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता तो इससे देश की अखंडता को अपूर्णीय क्षति हो सकती थी।

22. एस0डब्ल्यू0-2, श्री डी0 विजयकुमार, ईस्ट गारो हिल्स जिले के जिला मजिस्ट्रेट ने बयान दिया है कि ईस्ट गारो हिल्स जिले में उल्फा अत्यधिक सक्रिय रहा है और इसकी अवैध गतिविधियां जो वर्ष 2007 में प्रारम्भ हुई थीं, वर्ष 2008 में काफी बढ़ चुकी थीं। उन्होंने उल्लेख किया कि उल्फा ने कई अन्य अवैध संगठनों के साथ सम्बन्ध बना रखे थे और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (इसाक-मुईवाह) (एन0एस0सी0एन0-आई0एम0), लिबरेशन ऑफ ए'चिक इलाइट फोर्स (एल0 ए0ई0एफ0), पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (पी0एल0एफ0) और ए'चिक नेशनल वालन्टियर काउंसिल (ए0एन0वी0सी0) के साथ उसके सक्रिय सम्बन्ध थे। उल्फा के लक्ष्यों और उद्देश्यों, उल्फा द्वारा चलाई जा रही विधिविरुद्ध गतिविधियों और इस तथ्य कि ईस्ट गारो हिल्स जिले को, बांग्लादेशी राष्ट्रियों को भारतीय क्षेत्र में अवैध अप्रवासन करवाने के मार्ग के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, के सम्बन्ध में गवाह ने एस0 डब्ल्यू-1, डॉ0 श्रीरंजन के बयान का समर्थन किया है। गवाह ने साक्ष्य के रूप में अपना शपथ-पत्र अनुलग्नकों सहित प्रस्तुत किया है, जिसमें, अनुलग्नक-I से अनुलग्नक-VI प्रदर्श, प्रदर्श के रूप में एस0 डब्ल्यू-2/बी (समेकित रूप से), ईस्ट गारो हिल्स जिले में विभिन्न तारीखों को घटित घटनाओं के सम्बन्ध में अभिलेखों में रखी गई प्रथम सूचना रिपोर्टों और जब्ती ज्ञापनों की प्रतियों के साथ-साथ ईस्ट गारो हिल्स जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत किया गया एक चार्ट, जिसमें गवाह के शपथ-पत्र में उल्लिखित आपराधिक मामलों के सम्बन्ध में पुलिस रिकार्ड के उद्धरण दिए गए हैं, संलग्न किए गए हैं।

23. एस0डब्ल्यू0-3, श्री सिल्वेस्टर नांगटेंगर, ईस्ट गारो हिल्स, विलियमनगर के पुलिस अधीक्षक ने बयान दिया है कि दिनांक 21 फरवरी, 2009 का शपथ-पत्र उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है और यह कि उन्होंने साक्ष्य के रूप में सन्दर्भित शपथ-पत्र, अनुलग्नक -I से VI प्रदर्श, प्रदर्श के रूप में एस0 डब्ल्यू-3/सी (समेकित रूप से) के साथ प्रस्तुत किया है, सन्दर्भित अनुलग्नकों में, उल्फा के विरुद्ध दायर किए गए विभिन्न मामलों से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्टों और जब्ती ज्ञापनों की प्रतियां शामिल हैं। साक्ष्य के रूप में, उल्फा के विरुद्ध लम्बित मामलों का एक चार्ट भी संलग्न किया गया है। गवाह ने कहा है कि संगठन मुख्य रूप से पुलिस कार्मिकों सहित सरकारी अधिकारियों और व्यापारी

वर्ग के लोगों को निशाना बनाता था। संगठन का प्रमुख समर्थक नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (इसाक-मुईवाह) (एन०एस०सी०एन०-आई०एम०) था। इस संगठन द्वारा मुख्य रूप से हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था और हथियारों की आपूर्ति की जाती थी। एचिक नेशनल वालन्टियर काउंसिल (ए०एन०वी०सी०) और लिब्रेशन ऑफ एचिक इलाइट फोर्स (एल०ए०ई०एफ०) के साथ भी उल्फा के सक्रिय सम्बन्ध थे। उन्होंने उल्लेख किया कि हाल ही में उल्फा के सदस्यों में से एक, जिसका नाम पालिंग हाथो था, ने अपनी एम०-20 पिस्टल सहित मेघालय सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था।

24. एस०डब्ल्यू०-4, श्री एफ० आर० खरकोंगर, उपायुक्त, वेस्ट गारो हिल्स जिला, तूरा, मेघालय ने साक्ष्य के रूप में अपने दिनांक 24 अप्रैल, 2009 के शपथ-पत्र के साथ प्रदर्श ए०डब्ल्यू०-4/1 संलग्न किया है और यह उल्लेख किया है कि उन्होंने एस०डब्ल्यू०-5, श्री जे० एफ० के० मरक, पुलिस अधीक्षक, वेस्ट गारो हिल्स जिला, तूरा, मेघालय के शपथ-पत्र और उसके साथ संलग्न अनुलग्नकों का अध्ययन किया है और वह उससे पूर्ण रूप से सहमत हैं।

25. एस.डब्ल्यू. -5 श्री जे. एफ. के. मरक, पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी गारो हिल्स, जिला तूरा, मेघालय ने अपने दिनांक 21 फरवरी, 2009 में दिए गए साक्ष्य अनुलग्नक 'क' से 'ध' के रूप में एस.डब्ल्यू.-5/डी (समेकित रूप से) उनके जिले में उल्फा द्वारा चलाई जा रहे विभिन्न प्रकार विधिविरुद्ध क्रियाकलापों को प्रदर्शित करते हैं जिसमें यह बयान दिया गया है कि इसके गुट जिले में विशेष रूप से उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाली समग्र असम-मेघालय सीमा पट्टी पर अत्यधिक सक्रिय हैं। उन्होंने बताया कि उल्फा गारो हिल्स के नवगठित उग्रवादी गुटों जैसे मेघालय पिपुल्स लिब्रेशन फ्रंट (पी.एल.एफ.-एम.) और लिब्रेशन ऑफ एचिक इलाइट फोर्स (एल.ए.ई.एफ.) को हथियारों और गोला-बारूद की आपूर्ति करके और इन संगठनों के काडरों को प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी सक्रिय रूप से मदद कर रहा है, जो सामान्य तौर पर राज्य की सुरक्षा के लिए और विशेषकर जिले के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने आगे बताया कि पश्चिमी गारो हिल्स में उल्फा की आपराधिक गतिविधियों में जबरन वसूली, अपहरण, हत्या, अत्यधिक मात्रा में अवैध

हथियारों एवं गोला बारूद लाने-ले जाने जैसे अपराध शामिल हैं, और उपरोक्त प्रयोजनों के लिए उल्फा के कैडर अपने कैडर में स्थानीय युवकों को भर्ती करने का भरसक प्रयास कर रहे थे। उन्होंने यह भी बयान दिया कि उल्फा का संबंध बांग्लादेशी राष्ट्रियों के साथ था और वह अपने जिले का इस्तेमाल देश में घुसपैठ करने के लिए और आवश्यकता पड़ने पर उल्फा के सदस्यों को बांग्लादेश जाने के लिए एक कॉरीडोर के रूप में कर रहा था।

26. एस.डब्ल्यू.-6 श्री सुप्रिय कुमार राय, संयुक्त सचिव, गृह एवं राजनीतिक विभाग, असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी ने अपने शपथ पत्र में अनुलग्नकों सहित साक्ष्य दिया। उन्होंने अपने शपथ पत्र यह कहा कि उल्फा पर लगाए जा रहे सतत प्रतिबंधों के बावजूद यह संगठन, भारत की शान्ति, संप्रभुता और अखंडता को छिन्न-भिन्न करने और लोगों के बीच असुरक्षा की भावना पैदा करने की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के विधिविरुद्ध एवं हिंसा पूर्ण क्रिया कलापों संलिप्त रहा है। उनके अनुसार, दिनांक 27 नवम्बर, 2006 से 26, नवम्बर, 2008 तक की अवधि के दौरान उल्फा के कार्यकर्ता कुल 491 हिंसापूर्ण घटनाओं में संलिप्त पाए गए जिनमें कुल 224 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, 1027 व्यक्ति घायल हुए और फिरौती के लिए 12 व्यक्तियों का अपहरण किया गया। उपर्युक्त विशेष समय सीमा के दौरान उल्फा उग्रवादियों ने अन्य विघटनकारी गतिविधियां चलाने के साथ-साथ राज्य में 152 बम/ग्रेनेड विस्फोटों को अंजाम दिया। बम विस्फोटों की उक्त घटनाओं में 82 निदोष लोगों जिनमें 9 सुरक्षा बल कार्मिक शामिल हैं, की जानें गई और 966 व्यक्ति घायल हुए। उनके द्वारा उपर्युक्त घटनाओं की जिलेवार स्थिति को दर्शाने वाले विस्तृत चार्ट की एक प्रमाणिक प्रति, जिसमें मारे गए एवं घायल हुए व्यक्तियों के आंकड़ों को दर्शाया गया है, अनुलग्नक - 'ख' के रूप में प्रस्तुत की गई और और उन्होंने अपने शपथपत्र में इसके साथ-साथ उल्फा के प्रमुख विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के सार की एक प्रमाणिक प्रति भी अनुलग्नक 'ग' के रूप में प्रस्तुत की।

27. एस.डब्ल्यू.-6 श्री सुप्रिय कुमार राय ने अपने शपथपत्र में आगे उल्लेख किया कि उल्फा, बांग्लादेश और म्यांमार में अपने प्रशिक्षण शिविर चला रहा था जहां से वे असम के भू भाग में अपराध करके भाग जाने की रणनीति अपनाकर गुरिल्ला युद्ध नीति का संचालन और क्रियान्वयन कर रहे थे।

असम और अरुणाचल सीमा क्षेत्र में लखीमपुर, धेमाजी और तिनसुकिया जिलों और असम-मेघालय सीमा क्षेत्र में कामरूप, गोलपाड़ा और करबी अमलांग जिलों के समीपस्थ क्षेत्रों में प्रशिक्षण शिविर स्थापित किए हैं। उल्फा के उग्रवादी बांग्लादेश और म्यांमार में आने-जाने के लिए गुप्त मार्गों का उपयोग करते हैं। बांग्लादेश में रह रहे उल्फा के आकाओं ने पश्चिम बांकाकुश प्रशिक्षण शिविर में दिनांक 16 मार्च, 2008 को शेरपुर जिले की नई घाटी पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत और ढाका के मोती झील क्षेत्र में पश्चिम बांकापुरा प्रशिक्षण शिविर (बांग्लादेश) में अपनी इकाई का सैन्य दिवस मनाया और बोरोगजनी और बांकापुरा क्षेत्र में रह रहे काडरों ने भी इस समारोह में भाग लिया। परेश बरूआ (उल्फा के कमांडर इन चीफ) और बीजू देका ने बांकापुरा में काडरों को इकाई का सैन्य दिवस की महत्ता को स्पष्ट किया जबकि राजू बरूआ ने मोती झील में हुई जनसभा में परेश बरूआ (उल्फा के सी.एन.सी.) के भाषण को पढ़कर सुनाया। वर्ष 2008 में, उल्फा ने अपना स्थापना दिवस मनाया (अप्रैल 2007) और ढाका में परेश बरूआ (कमांडर-इन-चीफ, उल्फा) के फ्लैट में सेना दिवस मनाया (16 मार्च) जिसमें उल्फा के प्रमुख सेनानियों ने अपने परिवार के साथ भाग लिया। अरविन्द राजखोहा, अध्यक्ष, उल्फा ने समारोह में अध्यक्षीय भाषण पढ़ा। गवाह ने कहा कि पुलिस के समक्ष उपर्युक्त तथ्यों का रहस्योद्घाटन गिरफ्तार और आत्मसमर्पण कर चुके उल्फा सेनानियों द्वारा किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि उल्फा के सैनिकों को पाकिस्तान इन्टेलिजेन्स एजेंसी, इन्टर सर्विसेज इन्टेलिजेन्स (आई.एस.आई.) और डायरेक्टर जनरल ऑफ फील्ड इन्टेलिजेन्स, बांग्लादेश (संक्षिप्त नाम: डी.जी.एफ.आई.) द्वारा अब भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि असम राज्य के साथ-साथ भारत में राष्ट्र विरोधी एवं आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखा जा सके। गवाह ने यह भी बताया कि इस्लामिक आतंकवादियों के साथ उल्फा की दूरिभि संधि, डायरेक्टर जनरल ऑफ फील्ड इन्टेलिजेन्स (संक्षिप्त में डी.जी.एफ.आई. बांग्लादेश का बाहरी इन्टेलिजेन्स संगठन, बांग्लादेश राइफल्स (संक्षिप्तनाम: डी.डी.आर.) और आई.एस.आई.की वजह से राज्य के साथ-साथ समग्र भारत की आन्तरिक सुरक्षा परिदृश्य के लिए एक नई चुनौती पैदा की है। इस्लामिक उग्रवादियों ने उल्फा की मदद से गुवाहाटी से हवाई जहाज के अपहरण की योजना तैयार की थी। उल्फा पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य विद्रोही संगठनों नामतः कामतापुर लिबरेशन संगठन (के.एल.ओ.), मणिपुर लिबरेशन फ्रंट

(एम.पी.एल.एफ.) एवं त्रिपुरा पिपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट (टी.पी.डी.एफ.) के साथ संचालनात्मक जानकारी भी रखता रहा है। इसके अतिरिक्त, उल्फा, असम के लोगों को वर्ष 2007-2008 में गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) एवं स्वतंत्रता (15 अगस्त) का बहिष्कार करने के लिए और राज्य के इन दो विशिष्ट दिवसों पर आम हड़ताल करने का आह्वान करता रहा है। उल्फा द्वारा वर्ष 2008 में डेमाजी में शासकीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पी.टी.डी. विस्फोटक (प्रोग्रामेबल टाइम डिवाइस एक्सप्लोजिव) का प्रदर्शन किया गया जिसमें 13 व्यक्तियों, जिनमें 6 अवयस्क बच्चे शामिल थे, की मृत्यु हो गई। यह इकाई, इन्टरनेट और मीडिया के माध्यम से परिचालित पाक्षिक समाचार पत्र “फ्रीडम” द्वारा भारत विरोधी एवं सरकार विरोधी कार्यक्रम चलाती थी। इसके अलावा, उल्फा के नेतृत्व में बांकापुरा (बांग्लादेश) के प्रशिक्षण शिविर में काडरों को विस्फोटक-यथा पी.टी.डी. (प्रोग्रामेबल टाइम डिवाइस) आदि में महारथ हासिल करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। म्यांमार-चीन सीमा में उल्फा द्वारा अत्याधुनिक हथियारों के अधिअर्जन और राज्य में विघटनकारी गतिविधियों के लिए उन्हें समुद्री मार्ग से भेजने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया जिसके कारण राज्य की आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य के परिदृश्य में एक नई चुनौती जुड़ गई। उल्फा के आकाओं ने वहां से हथियारों की समुद्री मार्ग से भेजने के लिए क्षेत्र का सर्वेक्षण करने हेतु प्रबल नियोग और पार्थ गोगोई को भेजा। इसी प्रकार, उल्फा के उग्रवादियों ने अनेकों बार बांग्लादेश से असम अनेक छोटी-छोटी खेपों में मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स एवं दक्षिणी गारो हिल्स के गुप्त मार्गों से हथियार, गोला बारूद, ग्रेनेड, विस्फोटक आदि भेजे। उल्फा के कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न व्यक्तियों, व्यापारियों आदि को अपने पत्रशीर्ष में जबरन वसूली का नोटिस भेजकर 20 नवम्बर, 2007, 21 नवम्बर 2008 की अवधि के दौरान नोटिस भेजकर भारी धनराशि की जबरन वसूली की गई है। पुलिस द्वारा विभिन्न जिलों में उनके ठिकानों से और उल्फा के कैडरों से भेजे न जा सके जबरन वसूली के नोटिस और पत्रशीर्ष जब्त किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि उल्फा द्वारा की गई लूटपाट/जबरन वसूली के अनेक मामले पुलिस में रिपोर्ट ही नहीं किए जाते क्योंकि पीड़ित व्यक्ति उनके संगठनों द्वारा की जाने वाली बदले की भावना की आशंका की वजह से पुलिस में किसी प्रकार की औपचारिक रिपोर्ट कराने इच्छुक नहीं होता है। अलग-अलग मौकों पर जब्त किए गए हथियारों से यह पता चलता है कि उल्फा के पास अद्यतन अत्याधुनिक उन्नत

शस्त्रागार हैं जिससे उनकी मारक क्षमता में बढ़ोत्तरी हुई है। बांग्लादेश में स्थित उल्फा नेतृत्व ने अनेक विदेशी राष्ट्रों से अत्याधुनिक हथियारों/विस्फोटकों/गोलाबारूद और संचार उपकरणों की अधिप्राप्ति की अधिप्राप्त किए गए थे। ये हथियार मेघालय की सीमा और म्यांमार की झाझर सीमा और अन्य गुप्त मार्गों के माध्यम से असम को भेजे जाते थे जिससे कि असम में विघटनकारी गतिविधियां को जारी रखा जा सके। आसूचना रिपोर्ट से पता चला कि उल्फा संगठन, सेना/पुलिस/पी.एम.एफ.जांच चौकियों/गश्त दलों पर घात लगाने की पुनः तैयारी कर रहा है और इसके साथ-साथ आम लोगों तथा असम में हिन्दीभाषी जनसंख्या को निशाना बना रहा है।

28. एस.डब्ल्यू.-6 श्री एस.के. राय द्वारा दिए गए साक्ष्य में उल्फा के संविधान (अनुलग्नक-क) उल्फा के विधिविरुद्ध क्रियाकलाप का विस्तृत ब्यौरा (अनुलग्नक-ख) समेकित रूप से, उल्फा की प्रमुख विधिविरुद्ध गतिविधियों का सार (अनुलग्नक 'ग'), उल्फा काडरों (i) प्रबल नियोग (ii) अनन्त गोगई उर्फ शशांक बरूआ (iii) नोनी काकलरी उर्फ अनूप काकलरी एवं (iv) रंजीत कुमार राय हजांग उर्फ बाकुल राय एवं (v) मनि सैकिया उर्फ बाबू दत्त (अनुलग्नक-घ) से की गई पूछताछ बयान के प्रासंगिक सार की प्रमाणिक प्रति और उल्फा कैडर मनोज तामुली उर्फ रंदीप (अनुलग्नक-ड), से की गई पूछताछ के प्रासंगिक सारांश, दिनांक 20.1.2008 के 'फ्रीडम' समाचार पत्र के मुख-पृष्ठ की प्रमाणिक प्रति (अनुलग्नक-च समेकित रूप से) और उल्फा के पत्रशीर्ष पर वसूली पत्रों की प्रमाणित प्रतियां और उनका अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया गया।

29. गवाह के शपथ पत्र के साथ-साथ उपर्युक्त सभी अनुलग्नक अनुबंध 6/5 ड (समेकित रूप से) के रूप में प्रदर्शित हैं। उल्लेखनीय है कि इस गवाह ने यह बयान दिया है कि दिनांक 27 फरवरी, 2009 के शपथ पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात दिनांक 6 अप्रैल, 2009 को उल्फा के स्थापना दिवस के एक दिन पूर्व उल्फा ने मालेगांव क्षेत्र में अस्तित्व में आने के लिए वहां एक बम विस्फोट किया था। यह बम एक साईकिल में रखा गया था जो एक गहन आबादी क्षेत्र में पार्क की गई थी और इस विस्फोट के कारण 9 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 62 व्यक्ति घायल हुए इसमें से अधिकांश गम्भीर रूप से घायल हो गए। विस्फोट के कारण 15 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।

30 एस डब्ल्यू. 7 श्री प्रदीप चन्द्र सलोई, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुवाहाटी शहर ने अपने साक्ष्य में बताया कि दिनांक 18 फरवरी, 2009 का शपथ पत्र उनके द्वारा दिया गया था और उक्त शपथपत्र में अनुलग्नक-I से 24 तक के अनुलग्नक शासकीय अभिलेख से प्राप्त किए गए दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रति को प्रदर्श एस. डब्ल्यू. 7 एफ (समेकित रूप से) के रूप दर्शाया गया है। उन्होंने बयान दिया कि गुवाहाटी शहर और पूरे असम में उल्फा अत्यधिक सक्रिय था और बड़े पैमाने पर विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में संलिप्त था और राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ रहा था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अपने शपथ पत्र में उन्होंने अनेकों मामलों में से केवल आठ ऐसे मामलों का जिक्र किया जिनका सीधा संबंध उल्फा की अवैध गतिविधियों से है। उन्होंने बयान दिया कि उल्फा के काडरों की संलिप्तता पूर्णतः सिद्ध हो चुकी है और उनके राज्य में अभिलिखित है। उल्फा के काडर गुवाहाटी शहर में विघटनकारी गतिविधियां करने के लिए समय-समय पर गुवाहाटी शहर के अलग-अलग हिस्सों में ठिकाना बनाते हैं। एक मामला ऐसा भी है जिसमें वे उल्फा के ऐसे दो काडरों को पकड़ने में सफल हुए, जिन्होंने पूछताछ में बताया कि उन्होंने लोक प्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा (पूर्ववर्ती बोरझार हवाई अड्डा) से एक विमान अपहरण की योजना बनायी थी जिसे वे भूटान के रास्ते रावलपिंडी (पाकिस्तान) या अफगानीस्तान ले जाने चाहते थे। दोनों उल्फा काडरों ने उक्त अपराध को कारित करने की योजना बनाना स्वीकार किया था। गवाह ने आगे बताया कि उल्फा के कार्यकर्ताओं का संबंध श्रीलंका के एल.टी.टी.ई.) आतंकवादियों, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के आतंकवादियों एवं कट्टरपंथियों और विशेष रूप से आई.एस.आई. के साथ हैं। उन्होंने बताया कि चालू वर्ष के दौरान अर्थात् वर्ष 2009 में उल्फा के द्वारा गुवाहाटी शहर में छः विस्फोट किए गए। मालेगांव में 6 अप्रैल, 2009 को हुए विस्फोट में 9 व्यक्ति मारे गए और 62 व्यक्ति घायल हुए तथा अनेक वाहन क्षतिग्रस्त हुए।

31. एस. डब्ल्यू.-8 श्री देवा जीत हजारिका, पुलिस अधीक्षक, कामरूप जिला, असम ने अनुलग्नक सहित अपने शपथ पत्र में दिए साक्ष्य में यह बयान किया कि उल्फा के कार्यकर्ता उनके राज्य में व्यापक रूप से फैले हुए हैं जो बन्दूक की नोक पर जबरन वसूली, बम विस्फोट, अपहरण, अवैध हथियार एवं गोला बारूद तथा हत्या के प्रयास द्वारा लोगों को आतंकित करने के कार्यों में संलिप्त हैं।

उन्होंने उल्लेख किया कि उल्फा मुख्य रूप से राज्य के विरुद्ध जंग छेड़ रहा है और उनका संबंध कट्टरपंथी एवं आंतकवादी संगठनों यथा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडो लैण्ड (एन.डी.एफ.बी.) हजरत उल-मुजाहीदीन (एच.यू.एम.) एवं हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी (एच.यू.जे.आई.) के साथ है। उनके द्वारा दिए गए शपथ पत्र में राज्य में उल्फा की अवैध क्रियाकलापों की घटनाओं का स्पष्ट उल्लेख अनुलग्नक-1 एवं अनुलग्नक-14 के रूप में है। इस गवाह के अनुलग्नक युक्त शपथपत्र को एस.डब्ल्यू. 81 जी के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

32. एस.डब्ल्यू. -9 जितमल दोले, पुलिस अधीक्षक, नालबाड़ी जिला, असम ने दिनांक 18 फरवरी, 2009 को प्रस्तुत अपने शपथपत्र में यह बयान दिया कि उसमें उल्लिखित जानकारी उनके संज्ञान के अनुसार सत्य एवं सही है और अनुलग्नक 1 से 12 (समेकित रूप से) तक उसमें लगाए गए अनुलग्नक उनके जिले के शासकीय अभिलेखों की सत्य प्रमाणित प्रतियां हैं, और उक्त अनुलग्नक उनके जिले की घटनाओं से संबंधित हैं जिनमें उल्फा संलिप्त है और उल्फा की गतिविधियां पूर्णतः अभिलेखबद्ध हैं और इस बात के ठोस सबूत हैं कि उल्फा ही वह संगठन है जो इन जघन्य गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। उल्फा की विधिविरुद्ध एवं अवैध गतिविधियों में वसूली के लिए अपहरण, जबरन वसूली, राज्य की सुरक्षा बलों पर आक्रमण शामिल है, और वस्तुतः वह राज्य के विरुद्ध जंग छेड़ने की मुहिम चला रहा है जो यदि जारी रही तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। गवाह का अनुलग्नक युक्त शपथपत्र को प्रदर्श एस.डब्ल्यू.-9/एच के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

33. एस.डब्ल्यू.-10 श्री इमदाबुल हुसैन बोरा, पुलिस अधीक्षक, दरांग जिला, असम ने अनुलग्नक -1 से अनुलग्नक-XIII (क) युक्त अपने शपथ पत्र में साक्ष्य रूप में यह बयान किया कि विगत दो वर्षों के दौरान उल्फा जबरन वसूली, अवैध हथियार रखने और लोगों की हत्या करने की गतिविधियों में संलिप्त है, और यह कि उल्फा कैडर एक सूचीबद्ध कैडर हैं और उल्फा की गतिविधियां राज्य के विरुद्ध जंग छेड़ने की प्रकृति की हैं। उक्त गतिविधियां पूर्णतः सिद्ध और सुअभिलेखित हैं और निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि सभी कार्य उल्फा के ही हैं। इस गवाह का अनुलग्नक युक्त शपथ पत्र प्रदर्श एस.डब्ल्यू -10 के रूप में प्रदर्शित है।

34. एस.डब्ल्यू.-11 श्री टेक रिंगू, पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा पी.एच.क्यू. ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश के दिनांक 12 मार्च, 2009 के अनुलग्नक युक्त शपथ पत्र (I) तिरप (II) चामलांग (III) लोहित (IV) लोअर देबांग वैली एवं (V) पूर्वी सियांग जिलों में उल्फा द्वारा कारित घटनाओं से संबंधित हैं। इस गवाह का अनुलग्नक युक्त शपथ पत्र प्रदर्श एस.डब्ल्यू. -1 के 0 (समेकित रूप से) पर प्रदर्शित है। इस गवाह ने स्पष्ट रूप से बताया कि उल्फा द्वारा असम में जब भी किसी घटना को अंजाम दिया गया तो उसने अरुणाचल प्रदेश राज्य में आश्रय लिया और वहां भी उसके द्वारा सुरक्षा बलों एवं अन्य निर्दोष लोगों को मारकर एवं जबरन वसूली करके आतंक फैलाया गया। वस्तुतः उल्फा ने म्यांमार जाने के लिए अरुणाचल प्रदेश राज्य का उपयोग कॉरीडोर के रूप में किया है, जहां पर उनके कैम्प थे। गवाह ने बताया कि दिनांक 12 मार्च, 2009 को अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व उल्फा कैडर के एक व्यक्ति ने 10 मार्च, 2009 के आस-पास चामलांग जिले में हथियार एवं गोला बारूद के साथ आत्म समर्पण किया था। उन्होंने यह बयान किया कि चालू माह अप्रैल, 2009 में भी, ऐसी जानकारी मिली थी कि निचली देबांग घाटी जिले में उल्फा के कैम्प बने हुए हैं। ऐसी भी जानकारियां हैं कि वे लोग व्यापारी वर्ग, विशेषकर, गैर-स्थानीय लोगों से जबरन धन वसूली करते हैं, यह कि इनका संबंध नागालैण्ड के नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल खापलांग (एन.एस.सी.एन.के.) और अन्य गैर सामाजिक संगठनों के साथ है।

35. एस.डब्ल्यू. 12 - श्री अजय कुमार ओझा, अपर पुलिस अधीक्षक, तिराप जिला खोंसा, अरुणाचल प्रदेश ने अनुलग्नक युक्त अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो प्रदर्श एस डब्ल्यू-12/एल (समेकित रूप से) के रूप में है। उन्होंने बयान दिया है कि 15 अगस्त, 2008 को असम राइफल्स ने उल्फा संगठन के विमल गोगोई नामक एक सदस्य को तिराप जिले की कनूबारी बाजार से गिरफ्तार किया और उसके पास से ए.के. - 47 के चार सक्रिय कारतूस बरामद किए। इस संदर्भ में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम धारा 10/13 और इसके साथ पठित आर्म्स एक्ट की धारा 25(1) के तहत मामला सं० 8/2008 एफ.आई.आर. पुलिस स्टेशन कानूबारी में दर्ज किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि उल्फा ने तिराप जिला के अन्दर गंभीर पैठ बनाना प्रारंभ कर दिया है।

36. एस.डब्ल्यू. -13 श्री राकेन पादू, पुलिस अधीक्षक, पूर्वी शियांग जिला पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश ने यह बयान किया कि उनके द्वारा दिनांक 27.4.2009 को अनुलग्नक 'क' से (क) सहित शपथ पत्र दिया गया था। उन्होंने बताया कि उनके भू-भाग का प्रयोग उल्फा द्वारा इस क्षेत्र के साथ-साथ असम में अपराध कारित करने के पश्चात् भाग कर छुपने के स्थान के रूप किया जा रहा था। पूर्वी शियांग और लोअर देबांग घाटी जिला की सीमा पर स्थित गदाम तिनाली गांव के दो युवक श्री रंजीत पैट तथा जितेन मोरांग दिनांक 6.3.2008 को लापता हो गए। जंगलों में उनकी सघन तलाश की गई, परन्तु दोनों का पता नहीं चला। रंजीत पैट के पिता हैड कांस्टेबल ए.पी.पी. श्री बी. पैट को उल्फा के एस.एस.एल.टी मोहन बौरा उर्फ जितेन दत्ता की ओर से इस आशय की कॉल आई कि उनके पुत्र रंजीत पैट और बेहनोई जितेन मोरांग को सेना को सूचना प्रदान करने और उल्फा के विरुद्ध कार्य करने की वजह से मार दिया गया है। उनके शव बाद में नामसिंग ग्राम के जंगलों से बरामद किए गए जो देरी हो जाने के कारण खराब हो गए थे। इस संबंध में पुलिस स्टेशन पासीघाट में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 364/302/120 ख/201/34 के तहत मामला एफ.आई.आर. संख्या 39/09 दर्ज है। अपराधियों की मदद करने के लिए दुईमुख गांव से छः व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। उल्फा से सहानुभूति रखने वाले दो और लोग दिनांक 7.3.2008 से दुईमुख गांव से फरार हैं। पुलिस को इस आशय की चेतावनीभरी कॉल मिली है कि दुईमुख गांव से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार न किया जाए अन्यथा असम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों के बीच संघर्ष छिड़ जाएगा। उपर्युक्त धमकी की आशंका को देखते हुए पगलाम, नामसिंह और दुईमुख गांव के क्षेत्र में सघन गश्त की जा रही है और इसके लिए छानबीन कार्रवाई भी शुरू की गई। दुईमुख जंगल में छानबीन कार्रवाई के दौरान पुलिस द्वारा दवाईयां और बैटरी युक्त दो सोलर प्लेटें बरामद की गईं। इस गवाह का अनुलग्नक युक्त शपथ पत्र प्रदर्श एस.डब्ल्यू.-13 /एम. के रूप में प्रदर्शित किया गया।

37. एस.डब्ल्यू.-14 श्री किमि आया, पुलिस अधीक्षक, चांगलांग जिला, अरुणाचल प्रदेश ने कहा कि उनका दिनांक 27 अप्रैल, 2009 का शपथ पत्र उल्फा के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाय और उसके साथ संलग्न अनुलग्नक एवं शपथ पत्र शासकीय अभिलेख की सत्य प्रतियां हैं।

उन्होंने बताया कि उल्फा की प्रमुख गतिविधियां जबरन वसूली और लोगों की हत्या करना है और उल्फा का संबंध स्थानीय विद्रोही गुटों से है और वह चांगलॉग जिले का प्रयोग म्यांमार जाने और म्यांमार से वापस आने के लिए कॉरीडोर के रूप में कर रहा था। उल्फा द्वारा शिकार बनाए जाने वाले प्रमुख लोगों में व्यापारी वर्ग आता है जिनसे वह अपनी निधियां बढ़ाने के लिए जबरन वसूली करता था। “आयल इंडिया लिमिटेड” संगठन एवं इसके कर्मचारी गण उल्फा के दूसरे लक्ष्य थे। आम लोगों का इस्तेमाल वह संवाहक के रूप में किया करता था। 10 मार्च, 2009 के आस-पास उल्फा के एक काडर द्वारा चांगलॉग जिले में हथियारों, गोला बारूद, वॉकी-टाकी के साथ आत्मसमर्पण किया गया। इस गवाह का अनुलग्नक युक्त शपथपत्र प्रदर्श एस.डब्ल्यू.-14 /एन. के रूप में संलग्न है।

38. एस.डब्ल्यू -15 श्री तोजो कारगा, पुलिस अधीक्षक, जिला लोअर देबांग घाटी, रोइंग, अरुणाचल प्रदेश ने कहा की दिनांक 27 अप्रैल, 2009 को प्रस्तुत शपथ पत्र उनके द्वारा दिया गया था जिसके विवरण और विषय वस्तु उनके संज्ञान में सत्य और सही हैं और उसके साथ अनुलग्नक -वी. (समेकित रूप से) जिला देबांग लोअर घाटी, रोइंग, अरुणाचल प्रदेश के शासकीय अभिलेख की सत्य प्रतियां हैं। उन्होंने बयान किया है कि उनके जिले का इस्तेमाल उल्फा काडरों द्वारा अपना ऑपरेशन पूरा करने के बाद भाग छिपने के लिए किया जा रहा था, और यह कि उल्फा का संबंध अन्य प्रतिबंधित संगठनों, से है जिनमें नेशनल सोसलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) (एन.एस.सी.एन.-के) भी शामिल है। यह कि उल्फा के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध जनाक्रोश व्याप्त था, और यह कि वस्तुतः उल्फा द्वारा जनता में पैदा किए गए आतंक और उत्पीड़न की वजह से लोग रैलियां कर रहे थे जो उनके जिले में उसी तारीख अर्थात् दिनांक 27 अप्रैल, 2009 को निकाली गई। उन्होंने यह भी बयान किया कि अपने शपथ पत्र के साथ लगाए अनुलग्नक में उल्लिखित घटनाओं के अतिरिक्त मार्च, 2009 के अंतिम सप्ताह में राजस्थान के व्यापारी से जबरन वसूली की एक दूसरी घटना हुई। भय के कारण व्यापारी को अरुणाचल प्रदेश में अपने व्यापार ठप्प करके राज्य से भागना पड़ा। अनुलग्नकों सहित इस गवाह का शपथपत्र प्रदर्श एस.डब्ल्यू.-15/ओ.(समेकित रूप से) पर प्रदर्शित किया गया।

39. एस. डब्ल्यू. -16, श्री ईशाक परटिन, पुलिस अधीक्षक, लोहित जिला, तेजू, अरुणाचल प्रदेश ने बयान किया कि दिनांक 27 अप्रैल, 2009 को प्रस्तुत शपथ पत्र उनके द्वारा दिया गया था जिसके विवरण और विषयवस्तु उनके संज्ञान में सत्य और सही हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनके शपथ पत्र के साथ लगे अनुलग्नक उनके जिले के शासकीय अभिलेख की सत्य प्रतियां हैं। उन्होंने यह भी बयान किया कि असम राज्य में उल्फा द्वारा जब भी कोई आपरेशन कार्रवाई की जाती थी तो उनके जिले का इस्तेमाल भागकर छुपने के लिए किया जाता था और यह कि, उल्फा द्वारा इस प्रयोजनार्थ उनके जिले में अस्थायी शिविर बनाए गए थे। उल्फा का मुख्य उद्देश्य देश को अस्थिर करना था और इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए सुरक्षा बलों पर हमला करने और जबरन उगाही और निर्दोष लोगों की हत्या करने जैसी घृणित/जघन्य गतिविधियों द्वारा इसने लोगों में आतंक पैदा करना प्रारंभ कर दिया था। इसके द्वारा सुरक्षा बलों के लोगों और व्यापारिक वर्ग के लोगों को विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा था। एस.डब्ल्यू-16 ने बताया कि उल्फा का संबंध अन्य प्रतिबंधित संगठनों से भी है, जिसमें नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड - खापलांग (एन.सी.सी.एल.के.) जो राज्य में अत्यधिक सक्रिय संगठन है, भी शामिल है। इस गवाह का शपथपत्र, अनुलग्नकों सहित प्रदर्श एस.डब्ल्यू. 16/पी (समेकित रूप से) पर प्रदर्शित किया गया है।

40. दिनांक 26 और 27 अप्रैल, 2009 को शिलाँग में बैठक के दौरान किसी ने भी उल्फा का प्रतिनिधित्व नहीं किया और न ही उक्त तारीखों को जनसाधारण में से किसी ने जांच में भाग लिया। केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता श्री० बलदेव मलिक और श्री० शैलेंद्र शर्मा द्वारा किया गया, असम राज्य का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता श्री० अविजीत राँय, मेघालय का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता श्री० रंजन मुखर्जी द्वारा और अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता श्री० अनिल श्रीवास्तव द्वारा किया गया। मेघालय के पांच गवाहों, अरुणाचल प्रदेश के छः गवाहों, और असम राज्य के पांच गवाहों की गवाही शिलाँग में रिकार्ड की गई। इसके पश्चात क्रमशः मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के वकील ने अपनी गवाही पूरी की। असम राज्य के लिए विद्वान वकील द्वारा यह बयान दिया गया कि उन्हें बीस और गवाहों से पूछताछ करनी है जिन्हें बाद में गुवाहाटी में पेश किया जाएगा।

41. तदनुसार अधिकरण ने गुवाहाटी में असम राज्य के बाकी गवाहों की गवाही रिकार्ड करने के प्रयोजन से दिनांक 11 से 14 मई, 2009 तक गुवाहाटी में बैठकें की। उल्फा को विधि विरुद्ध संगठन घोषित करने वाली अधिसूचना के समर्थन में एस0डब्ल्यू0-17 से एस0डब्ल्यू0- 36 गुवाहाटी में गवाही देने के लिए उपस्थित हुए। यहां पर भी राज्यों के मामलों का खंडन करने के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और इस प्रकार शुरू से अंत तक किसी ने उल्फा का प्रतिनिधित्व नहीं किया। गुवाहाटी में एस0डब्ल्यू0-17 से एस0डब्ल्यू0- 36 गवाहों की प्रतिपरीक्षा की गई।

42. एस0डब्ल्यू0-17 श्री अरविंद कालिता, पुलिस अधीक्षक, जिला मोरीगांव, असम ने अपनी गवाही के दौरान कहा कि अनुलग्नकों सहित दिनांक 17 फरवरी, 2009 का शपथपत्र, प्रदर्श एस0डब्ल्यू0-17/क्यू0 (समेकित रूप में) उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। अपने उक्त शपथपत्र में उन्होंने उन आपराधिक गतिविधियों के बारे में बताया जिसमें उल्फा शामिल था, जिनकी मामला डायरियों से पुष्टि की गयी। गवाह ने कहा कि उल्फा का उद्देश्य उसके काडरों द्वारा हिंसक गतिविधियां जैसे कि बड़ी मात्रा में अपहरण, जबरन वसूली, हत्याएं, राष्ट्रीय ध्वज की अवमानना संबंधी गतिविधियां, डराना-धमकाना और नौजवानों की अपने संवर्ग में भर्ती करना, द्वारा असम को भारत से अलग करना था। उल्फा का आतंकवादी संगठनों, जैसे कामतापुर लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (के0एल0ओ0), पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर (पी0एल0ए0), ऑल त्रिपुरा टाईगर फोर्स (ए0पी0पी0एफ0), कार्बी-लॉंगरी नॉर्थ कचार हिल्स लिबरेशन फ्रंट (के0एल0एन0एल0एफ0) और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन0डी0एफ0बी0) के साथ संपर्क था। इसका संपर्क बांग्लादेश और पाकिस्तान (आई0एस0आई0) के साथ भी था।

43. एस0डब्ल्यू0-18, श्री श्रीमदन चेतिया, कमांडेंट, कमांडो बटालियन, उत्तरी गुवाहाटी ने गवाही देते हुए कहा कि दिनांक 18 फरवरी, 2009 का शपथपत्र अनुलग्नकों सहित प्रदर्श एस0डब्ल्यू0-18 /आर0 (समेकित रूप में) उनके द्वारा पेश किया गया था। उन्होंने अपने शपथपत्र में उल्फा की विधि विरुद्ध और अवैध गतिविधियों के बारे में बताया और कहा कि मामले की डायरियां ऊपर उल्लिखित अपराधों में उल्फा के सदस्यों का शामिल होना उजागर करती है। उन्होंने कहा कि

उल्फा का पूर्वोक्त में अन्य प्रतिबंधित संगठनों नामतः नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-खैपलांग गुट (एन०एस०सी०एन०-के०), ऑल त्रिपुरा टाईगर फोर्स (ए०टी०टी०एफ०) के साथ संपर्क था और पश्चिमी पाकिस्तान एवं बांग्लादेश दोनों में आई०एस०आई० के साथ भी गठजोड़ था।

44. एस०डब्ल्यू०-19, श्री श्रीराणा भुयन, पुलिस अधीक्षक, जिला बक्सा, मुशालपुर (बी०टी०ए०डी०), असम ने अनुलग्नकों सहित अपने शपथपत्र प्रदर्श एस०डब्ल्यू०-19/एस० (समेकित रूप में) के मामले में बयान दिया। अपने उपरोक्त शपथपत्र में, उन्होंने भी उल्फा द्वारा की जा रही विधि विरुद्ध और अवैध गतिविधियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उल्फा सार्वजनिक स्थानों पर बम विस्फोटों, हत्या, अपहरण, जबरन वसूली इत्यादि में शामिल था, इसका अन्य प्रतिबंधित संगठनों जैसे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन०डी०एफ०बी०), कामतापुर लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (के०एल०ओ०) और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-इसाक मुईवाह गुट (एन०एस०सी०एन०-आई०एम) के साथ संपर्क था। इसके अलावा उल्फा का बांग्लादेश और आई०एस०आई० के साथ सक्रिय संपर्क था।

45. एस०डब्ल्यू०-20, श्री लचित बरूआ, पुलिस अधीक्षक, जिला बोंगाईगांव, असम ने विटनेस बॉक्स में बयान दिया कि अनुलग्नकों सहित उनका शपथपत्र जिसे समग्र रूप से प्रदर्श एस०डब्ल्यू०-20/टी० के रूप में चिह्नित किया गया था, उनके अनुसार सच और सही है। उन्होंने बयान दिया कि उल्फा समाज विरोधी और विधिविरुद्ध गतिविधियों जैसे फिरौती के लिए अपहरण, जबरन वसूली, बम विस्फोटों और हत्याओं में शामिल था और इसका उद्देश्य लोगों में डर पैदा करना था ताकि उन्हें आतंकित किया जा सके और इस प्रकार आतंकवादी गतिविधियों को अन्जाम दिया जाए। उन्होंने यह बयान भी दिया कि उल्फा का अन्य प्रतिबंधित और आतंकवादी संगठनों जैसे कामतापुर लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (के०एल०ओ०), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन०डी०एफ०बी०), पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर (पी०एल०ए०), कार्बी-लॉंगरी नॉर्थ कचार हिल्स लिबरेशन फ्रंट (के०एल०एन०एल०एफ०) और पड़ोसी देश पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में विभिन्न कट्टरवादी गुटों के साथ सक्रिय संपर्क थे।

46. एस0डब्ल्यू0-21, श्री पार्थ सारथी मंहत, पुलिस अधीक्षक, जिला धुबरी, असम ने अपने साक्ष्य प्रदर्श एस0डब्ल्यू0-21/यू.(समेकित रूप में) में अनुलग्नकों सहित अपना शपथपत्र पेश किया और उल्फा की अवैध गतिविधियों के बारे में बयान दिया, जिसके संबंध में उनके द्वारा अपने शपथपत्र में घटनाओं का भी उल्लेख किया गया था। उन्होंने कहा कि उल्फा प्रायः बम विस्फोट करता था जिसके परिणामस्वरूप मनुष्यों की जानें जाती थीं और यह अपहरण, जबरन वसूली, हत्या और वास्तव में मानव जीवन को खतरे में डालने के लिए रचित प्रत्येक गतिविधि में भाग लेता था। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन.डी.एफ.बी.), कामतापुर लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (के.एल.ओ), कार्बी-लॉंगरी नॉर्थ कचार हिल्स लिबरेशन फ्रंट (के.एल.एन.एल.एफ) और ऑल त्रिपुरा टाईगर फोर्स (ए.पी.पी.एफ) के साथ इसके सक्रिय संपर्क थे। इसके अलावा, विदेशी ताकतों और संगठनों तथा विशेषकर पाकिस्तान और बांग्लादेश में आई0एस0आई0 के साथ भी इसके संपर्क थे।

47. एस0डब्ल्यू0-22, श्री दीपक चौधरी, पुलिस अधीक्षक, जिला जोरहाट, असम ने सशपथ बयान दिया कि उनका दिनांक 17 फरवरी, 2009 का शपथपत्र अनुलग्नकों सहित प्रदर्श एस0 डब्ल्यू0-22/वी. (समेकित रूप में) है। उन्होंने बयान दिया कि उल्फा का लक्ष्य राज्य के विरुद्ध युद्ध शुरू करके और हिंसक साधनों द्वारा जैसे बम्ब विस्फोट, फिरौती के लिए अपहरण, जबरन वसूली, निर्दोष व्यक्तियों की हत्या और वास्तव में जो शांति और सौहार्द प्रिय व्यक्तियों की हत्या करके असम को भारत से अलग करना है। उसने बयान दिया कि असम में उल्फा का अन्य प्रतिबंधित संगठनों जैसे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खैपलांग गुट)(एन.एस.सी.एन.-के), कामतापुर लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (के0एल0ओ0) और ऑल त्रिपुरा टाईगर फोर्स (ए0पी0पी0एफ0) के साथ संपर्क थे। इसके विभिन्न देशों के साथ भी संपर्क थे जिसका मुख्य बेस बांग्लादेश था। इसके काइरों को पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आई0एस0आई0 के साथ प्रशिक्षित किया गया।

48. एस0डब्ल्यू0-23, श्री अखिलेश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक, जिला गोलपाड़ा, असम ने अपने साक्ष्य में अपना दिनांक 17 फरवरी, 2009 का शपथपत्र अनुलग्नकों सहित प्रदर्श एस0 डब्ल्यू0-23/डब्ल्यू (समेकित रूप में) प्रस्तुत किया और उल्फा की अलगाववादी गतिविधियों के बारे में बयान दिए, उन्होंने कहा कि यह बम विस्फोटों, हिंदी भाषी व्यक्तियों की हत्या, बड़ी मात्रा में जबरन

वसूली और सुरक्षा कार्मिकों पर बड़ी मात्रा में आक्रमण के जरिए देश के विरुद्ध युद्ध आरम्भ कर रहा था। इसके नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन.डी.एफ.बी.), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खैपलांग गुट)(एन.एस.सी.एन.-के) तथा कामतापुर लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (के.एल.ओ.), जोकि भारतीय उग्रवादी संगठन है, के साथ संपर्क थे। इसके संबंध विदेशी ताकतों जैसे पश्चिम पाकिस्तान में आईएसआई और बांग्लादेश के साथ भी थे।

49. एस0डब्ल्यू0-24, श्री देवज्योति मुखर्जी, पुलिस अधीक्षक, जिला बारपेटा, असम ने अपने साक्ष्य में अनुलग्नकों सहित अपने शपथपत्र को प्रदर्श एस0डब्ल्यू0-24/एक्स (समेकित रूप से) प्रस्तुत किया और उल्फा की अलगाववादी एवं आपराधिक गतिविधियों के बारे में अपने शपथपत्र में विशेष घटनाओं का उल्लेख किया गया। उन्होंने पहले गवाहों के बयानों का समर्थन किया कि उल्फा का संपर्क अन्य प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों एवं आईएसआई एवं अन्य देशों जैसे अफगानिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ था।

50. एस0डब्ल्यू0-25, श्री अनुराग अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा (जी) ने शपथ बयान दिया कि उनका 18 फरवरी, 2009 का शपथपत्र उन्होंने प्रस्तुत किया था और शपथपत्र के साथ अनुलग्नक उन दस्तावेजों की सत्य प्रतियां थी जो जिले के कार्यालय रिकार्डों से लिए गए थे (जिन्हें समग्ररूप से प्रदर्श एस0डब्ल्यू0-25/वाई के रूप में चिन्हित किया गया है) उन्होंने विधिविरुद्ध गतिविधियों की विभिन्न घटनाओं को दर्शाया है जिसमें उल्फा शामिल था, जैसे कि बम विस्फोट, निर्दोष व्यक्तियों की सामूहिक हत्या, जबरन वसूली, आपराधिक अभिवास और हिंदी भाषी व्यक्तियों की हत्या। उन्होंने बयान दिया कि उल्फा का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन0डी0एफ0बी0), कामतापुर लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (के0एल0ओ0), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खैपलांग गुट)(एन0एस0सी0एन0के) और ऑल त्रिपुरा टाईगर फोर्स (ए0टी0टी0एफ0) जो सभी भारत में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन थे, के साथ संपर्क था। इसका विदेशी उग्रवादी संगठनों जैसे आईएसआई के साथ भी संपर्क था और इसके काडरों को बांग्लादेश, पश्चिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में प्रशिक्षित किया गया था।

51. एस0डब्ल्यू0-26, श्री आनन्द प्रकाश तिवारी, पुलिस अधीक्षक, जिला उदलगुरी, असम ने इसके पश्चात् अपने साक्ष्य में अपने शपथपत्र और अनुलग्नकों को प्रदर्श एस0डब्ल्यू0-26/जेड0 (समेकित रूप में) पेश करने के लिए और यह कहने के लिए कि उनके शपथपत्र में उल्फा की अवैध गतिविधियों के बारे में दिए गए उदाहरण उनके संज्ञान में सत्य एवं सही थे और उनके शपथपत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक जिले के कार्यकारी रिकार्डों से लिए गए थे, विटनेस बॉक्स में उपस्थित हुए। उन्होंने बयान दिया कि उल्फा का लक्ष्य और आदर्श सभी प्रकार की विद्रोही गतिविधियों द्वारा असम को एक अलग और सार्वभौमिक राज्य बनाना था। उन्होंने गांव भगतपाड़ा के मुखिया का उदाहरण दिया जिसे हाल ही में उल्फा काडरों द्वारा गोली मार दी गई थी। उन्होंने कहा कि उल्फा का संपर्क पश्चिम पाकिस्तान और बांग्लादेश में आई0एस0आई0 के अलावा अन्य प्रतिबंधित संगठनों जैसे कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खैपलांग गुट)(एन0एस0सी0एन0-के), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन.डी.एफ.बी.) एवं झारखंड के माओवादियों से थे। जघन्य कार्यों को अंजाम देने के लिए उल्फा काडरों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं नेपाल में प्रशिक्षित किया जाता था।

52. एस0डब्ल्यू0-27, श्री कृष्ण कुमार शर्मा, पुलिस अधीक्षक, कारबी अंगलांग, असम ने अपने दिनांक 18 फरवरी, 2009 के शपथपत्र और इसके संलग्नकों की विषय-वस्तु की पुष्टि की, इसमें विधिविरुद्ध और अवैध गतिविधियों में उल्फा के शामिल होने के उदाहरण दिए [प्रदर्श एस0डब्ल्यू0-27/ए0ए0(समेकित रूप में)]। विशेष रूप से उन्होंने बयान दिया कि उल्फा रैंकों के मुखिया बांग्लादेश में थे और इनके बांग्लादेश एवं पश्चिम पाकिस्तान में आई0एस0आई0 के साथ संपर्क थे। उल्फा काडरों को बांग्लादेश और पश्चिम पाकिस्तान में प्रशिक्षित किया जा रहा था। भारत में उल्फा के अन्य प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों जैसे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन0डी0एफ0बी0) और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-इसाक-मुइवाह (एन0एस0सी0एन0-आई0एम0) के साथ संपर्क थे। उनकी पूछताछ रिपोर्टों से, यह स्पष्ट था कि उल्फा अलगाववादी गतिविधियों में शामिल था जोकि असम राज्य की शांति और सुरक्षा के लिए हानिकारक थी।

53. एस0डब्ल्यू0-28, श्री सुरेन्द्र कुमार, पुलिस अधीक्षक, सोनितपुर, असम ने बयान दिया कि उनका दिनांक 18 फरवरी, 2009 का शपथपत्र इसके अनुलग्नकों सहित जिसे समग्र रूप से प्रदर्श एस0डब्ल्यू0-28/बी0बी0 के रूप में चिन्हित किया गया है उनके संज्ञान में सत्य एवं सही है। उन्होंने बयान दिया कि उन्होंने उल्फा की गतिविधियों के संबंध में अपने शपथपत्र में कुछ मामलों का उल्लेख किया था, जो स्पष्ट रूप में इस तथ्य को सिद्ध करते हैं कि उल्फा सशस्त्र संघर्ष और आतंकवादी गतिविधियों के जरिए एक स्वतंत्र पृथक राज्य के सृजन में शामिल था। उल्फा का संपर्क नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन0डी0एफ0बी0), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खैपलांगगुट) (एन0एस0सी0एन0-के), कामतापुर लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (के0एल0ओ0) और अन्य प्रतिबंधित संगठनों और विशेषकर पश्चिम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में आई0एस0आई0 के साथ था।

54. एस0डब्ल्यू0-29, श्री श्यामल प्रसाद सैकिया, पुलिस अधीक्षक, जिला शिवसागर, असम ने अपने शपथपत्र की विषय-वस्तु की पुष्टि की, जिसे इसके अनुलग्नकों सहित समग्र रूप से प्रदर्श एस0डब्ल्यू0-29/सी0सी0 के रूप में चिन्हित किया गया है। उन्होंने बयान दिया कि उनके जिले में उल्फा बड़ी मात्रा में जबरन वसूली और गैर असमी व्यक्तियों, विशेषकर हिंदी भाषी व्यक्तियों की हत्या और राज्य के बाहर से आए व्यक्तियों की हत्या में शामिल था। उन्होंने आगे बयान दिया कि उन्होंने कुछ मामलों के उदाहरण दिए हैं जिसमें यह तथ्य स्पष्ट है कि उल्फा उनके जिले में अवैध और विधि विरुद्ध गतिविधियों में शामिल था। उदाहरणार्थ, दिनांक 16 फरवरी, 2008 में उनके द्वाग चलाए गए एक अभियान में उल्फा से हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए और जो स्पष्ट रूप से उल्फा उग्रवादियों का देश के विरुद्ध विद्रोही और विधिविरुद्ध गतिविधियों में शामिल होना दर्शाता है। मुठभेड़ के दौरान पांच उल्फा काडरों में से चार मारे गए जबकि एक भागने में सफल हुआ। दिनांक 10 जून, 2008 को एक अन्य अभियान में उनके जिले की पुलिस और सेना को गोली चलानी पड़ी और एक उल्फा उग्रवादी मारा गया जबकि उसका एक साथी नामतः, आदित्य नायडू बनाम तरुण बनाम कर्मा पांडे को सेना कर्मियों ने गिरफ्तार कर लिया था। विश्वसनीय जानकारी के आधार पर, दिनांक 15 जून, 2008 को, उल्फा उग्रवादियों के विरुद्ध एक अन्य अभियान चलाया गया जिसके परिणामस्वरूप

उल्फा काडर के कुछ व्यक्ति मारे गए और हथियार एवं गोलाबारूद बरामद किए गए। गवाह ने इस बात की भी पुष्टि की कि उल्फा जोकि असम राज्य और भारत संघ के विरुद्ध युद्ध आरंभ कर रहा था, के संपर्क, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एन०एस०सी०एन०), कार्बी-लॉंगरी नॉर्थ कचार हिल्स लिबरेशन फ्रंट (के०एल०एन०एल०एफ०) और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन०डी०एफ०बी०) एवं पश्चिम पाकिस्तान और बांग्लादेश में आई०एस०आई० के साथ थे।

55. एस०डब्ल्यू०-30, श्री सत्यराज हजारिका, पुलिस अधीक्षक, धेमाजी, असम, श्री के.जे. सेकिया, पूर्व पुलिस अधीक्षक, जिला धेमाजी जो चिकित्सा कारणों से गवाही देने के लिए उपस्थित होने में असमर्थ थे, का शपथपत्र प्रस्तुत करने हेतु विटनेस बॉक्स में उपस्थित हुए। उक्त शपथपत्र को इसके अनुलग्नकों सहित प्रदर्श एस०डब्ल्यू०-30/डी.डी. (समेकित रूप में) पर दर्शाया गया था जिस पर गवाह ने शपथपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर श्री कंगकन ज्योति सैकिया के हस्ताक्षरों की पहचान की। गवाह ने कहा कि दिनांक 30 मई, 2007 और 3 अप्रैल, 2008 को घटित घटनाओं के संबंध में शपथपत्र में दिए गए दो मामलों ने उल्फा का विघटनकारी और अवैध गतिविधियों में शामिल होना सिद्ध किया, यद्यपि यह केवल उदाहरणार्थ था, चूंकि उल्फा के विरुद्ध कई अन्य मामले लंबित पड़े थे और उनकी संलिप्तता पूर्ण विदित एवं पूर्ण स्थापित थी। उन्होंने बयान दिया कि उल्फा भारत में अन्य प्रतिबंधित संगठनों जैसे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन०डी०एफ०बी०), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एन०एस०सी०एन०) और कामतापुर लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (के०एल०ओ०) के अलावा आई०एस०आई० के साथ गहन संपर्क में कार्य कर रहा था और इसके अफगानिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार में शिविर थे।

56. एस०डब्ल्यू०-31, श्री ए० डेका, पुलिस अधीक्षक, जिला चेरांग, असम, ने अनुलग्नकों सहित अपने शपथपत्र के विषयवस्तु की पुष्टि की जिसे एस०डब्ल्यू०-30/ई०ई० के रूप में चिन्हित किया गया था। उन्होंने उल्फा के लक्ष्य और उद्देश्यों के बारे में बयान दिया कि इसका उद्देश्य हिंसक साधनों और अपहरण, निर्दोष व्यक्तियों की हत्या, बम विस्फोट और इसके जैसे अन्य कार्यों द्वारा भारत संघ से अलग होना है। उन्होंने कहा कि उनके शपथपत्र में उल्लिखित मामलों से यह स्पष्ट होता है कि उनके

राज्य में उत्फा विघटनकारी गतिविधियों में शामिल है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उक्त मामले उदाहरणार्थ हैं और सीमित नहीं हैं क्योंकि उनके जिले में उत्फा के विरुद्ध कई मामले थे। उत्फा का कामतापुर लिब्रेशन ऑर्गनाइजेशन (के०एल०ओ०), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एन०एस०सी०एन०), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन०डी०एफ०बी०) के साथ संपर्क था और बांग्लादेश एवं पश्चिम पाकिस्तान के आई०एस०आई० के साथ गहन संबंध था।

57. एस०डब्ल्यू०-32, श्री सैयद अतुल करीम, पुलिस अधीक्षक, जिला लखीमपुर, असम, ने साक्ष्य में अनुलग्नकों सहित अपने शपथपत्र, जिसे प्रदर्श ए०डब्ल्यू०-32/एफ०एफ० (समेकित रूप में) के रूप में चिन्हित किया गया है, को पेश करने के लिए और यह बयान देने के लिए विटनेस बॉक्स में उपस्थित हुए कि उत्फा एक अलगाववादी, उग्रवादी संगठन था जोकि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने में शामिल था और निर्दोष व्यक्तियों की हत्या, विशेषकर हिंदी भाषियों की हत्या, व्यापारियों की हत्या, सुरक्षा कर्मियों और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की हत्या में लिप्त था। उन्होंने कहा कि उन्होंने उत्फा के अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने को सिद्ध करने के लिए अपने शपथपत्र में केवल तीन मामलों का उल्लेख किया। राजा बरूआ, जिसे उक्त मामलों में से एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, एक उत्फा उग्रवादी था और उसका रिकार्ड किया गया बयान जिसमें उक्त तथ्य के बारे में बताया गया था, उनके द्वारा अपने शपथपत्र के साथ संलग्न किया गया। उन्होंने आगे कहा कि दिनांक 07.04.2008 को लगभग सुबह चार बजे अर्थात् उत्फा के स्थापना दिवस को उत्फा कार्यकर्ताओं द्वारा घिलामारा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कालाबारी तिनयाली जिले की पुलिस द्वारा उत्फा चिन्ह (मध्य में आधा निकला सूरज) वाला उत्फा झंडा पाया गया जिसका उद्देश्य भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध आरंभ करने के आपराधिक षडयंत्र और असम को भारत संघ से अलग करना दर्शाना था। उक्त झंडा एक जब्ती ज्ञापन द्वारा जब्त किया गया, जो उनके द्वारा अपने शपथपत्र के साथ संलग्न किया गया था। गवाह ने आगे बयान दिया कि उत्फा का भारत और विदेशों में अन्य प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों जैसे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन.डी.एफ.बी.), कामतापुर लिब्रेशन ऑर्गनाइजेशन (के.एल.ओ.) और लिब्रेशन टाईगर्स ऑफ तमिल ईलम (एल०टी०टी०ई०) के साथ संबंध था। इसका संपर्क, विदेशों नामतः बांग्लादेश, भूटान, पश्चिम पाकिस्तान और म्यांमार के साथ

था, जहां इसके कांडर प्रशिक्षण और शरण लेते थे। इसका नेपाल में माओवादियों और पश्चिम पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद जिसे आई०एस०आई० का समर्थन प्राप्त था, के साथ भी संबंध था।

58. एस०डब्ल्यू०-33, श्री नितुल गोगई, पुलिस अधीक्षक, जिला नागांव, असम, ने सोलह अनुलग्नकों सहित अपने दिनांक 18 फरवरी, 2009 के शपथपत्र की विषयवस्तु की पुष्टि की जिसे प्रदर्श एस०डब्ल्यू०-33/जी०जी० (समेकित रूप में) पर दर्शाया गया है। उन्होंने बयान दिया कि उनके शपथपत्र को उल्फा के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में माना जाए, जिसका मुख्य लक्ष्य शांतिप्रिय लोगों में आतंक फैलाकर और बम विस्फोट करके, फिरौती के लिए अपहरण, सरकारी कर्मचारियों और व्यापारी वर्ग और वास्तव में उन सभी व्यक्तियों जो उनकी विचारधारा का समर्थन नहीं करते की हत्या और आपराधिक अभिवास द्वारा असम को भारत संघ से अलग करना था। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने शपथपत्र में चार मामलों का उल्लेख किया था जो स्पष्ट रूप से उल्फा की संलिप्तता दर्शाते हैं परन्तु उक्त मामले केवल उदाहरणार्थ हैं और यहीं तक सीमित नहीं हैं। उल्फा के भारत में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एन०एस०सी०एन०), कामतापुर लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (के०एल०ओ०) और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन०डी०एफ०बी०) और पाकिस्तान में आई०एस०आई० के साथ सक्रिय संपर्क थे। उनके शिविर बांग्लादेश में स्थित थे और उन्होंने अफगानिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान में प्रशिक्षण लिया।

59. एस०डब्ल्यू०-34, श्री बान्या गोगई, पुलिस अधीक्षक, विशेष अभियान यूनिट (एस० ओ० यू०), असम, दिसपुर, गुवाहाटी ने अपने साक्ष्य में अपने शपथपत्र को प्रदर्श एस०डब्ल्यू०-34/एच०एच० (समेकित रूप में) को पेश किया और कहा कि शपथपत्र और श्री एस० के० रॉय, संयुक्त सचिव, गृह और राजनीतिक विभाग, असम सरकार (एस०डब्ल्यू०-6) के शपथपत्र के साथ संलग्न अनुलग्नकों की विषयवस्तु सत्य एवं सही थी। अपने बयान में इस गवाह ने सभी जिलों और अपने स्वयं के स्त्रोतों से आसूचना एकत्र करके उल्फा की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने में विशेष शाखा की भूमिका का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि सभी जिला पुलिस अधीक्षकों ने उल्फा की गतिविधियों के बारे में प्राप्त जानकारी की रिपोर्ट उनकी शाखा को दी, और विशेष शाखा को जब भी

उल्फा गतिविधियों के संबंध में आसूचना की जरूरत पड़ी तो उन्होंने इसे उल्फा के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाई करने के लिए जिलों को भेजा और उच्च प्राधिकारियों अर्थात् पुलिस मुख्यालय और असम सरकार को भी जानकारी भेजी। गवाह ने आगे कहा कि उल्फा का लक्ष्य और उद्देश्य देश के विरुद्ध युद्ध करके और भारत सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष द्वारा असम को स्वतंत्र करना था। उल्फा म्यांमार के ऊपरी भाग एवं बांग्लादेश में शेरपुर जिले में प्रशिक्षण शिविर चला रहा था। गवाह ने कहा कि वर्ष 2008 में जैसाकि उनके शपथपत्र में दर्शाया गया है, दो आत्मसमर्पित उल्फा संवर्गों जिनके बयान एस0डब्ल्यू0-6 श्री एस0के0 रॉय के शपथपत्र के साथ संलग्न थे, से प्राप्त सूचना के अनुसार उल्फा के बांग्लादेश के शेरपुर में प्रशिक्षण शिविर और ढाका में श्री परेश बरूआ के फ्लैट में अपना स्थापना दिवस और सेना दिवस मनाया। गवाह ने आगे कहा कि उल्फा अभी भी अपनी भर्ती अभियान जारी रखे हुए था और उसने राज्य के अलग-अलग भागों से बड़ी संख्या में नौजवानों की भर्ती की, जिन्हें पाकिस्तान में आई0एस0आई0 और बांग्लादेश में डी0जी0एफ0आई0 जैसी विदेशी एजेंसियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा था। यह प्रशिक्षण उल्फा को आतंकवादी गतिविधियां चलाने के लिए दिया जा रहा था। गवाह ने उल्फा और इस्लामिक उग्रवादियों जिन्होंने इकट्ठे गुवाहाटी से एक वायुयान के अपहरण की योजना बनाई, के बीच संपर्क को भी उजागर किया। इस संदर्भ में उल्फा काडरों के बयान रिकार्ड किए गए और एस0डब्ल्यू0-6, श्री एस0के0 रॉय के शपथपत्र में शामिल किए गए। गवाह ने आगे बयान दिया कि उल्फा नियमित रूप से असम के लोगों को गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस का विरोध करने और राज्य में इन दो विशेष दिवसों पर हड़ताल करने के लिए कहता रहा है। हत्या के लिए आक्रमण, बम विस्फोट, अपहरण, जबरन वसूली, सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति का बड़ी मात्रा में विनाश और एक के बाद एक हत्या में उल्फा की संलिप्तता दर्शाने वाले विस्तृत चार्ट सहित इस संबंध में स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचारों की पेपर क्लिपिंग भी एस0डब्ल्यू0-6, श्री एस0के0 रॉय के शपथपत्र के साथ संलग्न की गई। गवाह ने कहा कि उल्फा का मुखपत्र "फ्रीडम" था। इस प्रकाशन की विषयवस्तु राज्य के विरुद्ध युद्ध आरंभ करने से संबंधित थी और लेखों का प्रकाशन उल्फा काडरों का आत्मबल बढ़ाने के लिए था। गवाह के अनुसार व्यापक रूप में देखने पर यह गतिविधियां उल्फा द्वारा युद्ध आरंभ करने के लिए और राष्ट्र की संप्रभुता पर आक्रमण करने और देश

के राष्ट्रीय स्रोतों जैसे तेल क्षेत्र, भूतल परिवहन और संचार नेटवर्क को निशाना बनाने के लिए तैयार की गई थीं। पिछले तीन या चार वर्षों में उनका जोर विस्फोटकों द्वारा भीड़-भाड़ वाले मार्गों, भीड़ वाले बाजारों और व्यापारिक केन्द्रों को लक्ष्य बनाकर विस्फोटकों द्वारा बड़ी संख्या में निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करना था, क्योंकि उनका लक्ष्य सुखियों में आना था।

60. एस.डब्ल्यू-34, सुश्री बान्या गोगोई ने भी दिनांक 31 मार्च, 2009 तथा 6 अप्रैल, 2009 को गुवाहाटी में हाल ही में हुई बम विस्फोट की ऐसी दो घटनाओं के बारे में; उल्फा के ऑल त्रिपुरा टाईगर फोर्स (ए.टी.टी.एफ.), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैण्ड (एन.डी.एफ.बी.), पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर (पी.एल.ए.), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (खापलांग गुट) (एन.एस.सी.एन.-के) तथा कामतापुर लिबरेशन आर्गेनाइजेशन (के.एल.ओ.) के साथ संबंध होने के बारे में बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह, पश्चिम बंगाल के उत्तरी बंगाल कॉरिडोर में सक्रिय था। गवाह ने आगे बताया कि पाकिस्तान की आई.एस.आई. तथा बांग्लादेश की डी.जी.एफ.आई. भी उल्फा तथा उसकी गतिविधियों को सक्रिय समर्थन दे रही थी। उल्फा के प्रमुख तथा इसकी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य पहले से ही बांग्लादेश में थे तथा असम सरकार को इसके बारे में पुरख्ता जानकारी थी कि बांग्लादेश की भूतपूर्व सरकार उल्फा के काडरों को सक्रिय एवं संभारतंत्रीय समर्थन दे रही है। गवाह के अनुसार उल्फा को गतिविधियों संबंधी दिशानिर्देश बांग्लादेश में बैठे आकाओं से आए थे तथा मध्यम स्तर एवं निम्न स्तर के कैडरों ने असम राज्य में उन्हें अंजाम दिया। यह तथ्य कि उल्फा काडरों ने विदेशों में शरण ली थी, से यह पता चलता है कि उल्फा को बांग्लादेश तथा पाकिस्तान जैसे देशों ने सक्रिय सहयोग दिया अन्यथा उल्फा के काडर उक्त देशों में टिक नहीं सकते थे।

61. एस0डब्ल्यू0-34, सुश्री बान्या गोगोई ने दिनांक 11, 12, 13 तथा 14 मई, 2009 को गुवाहाटी में हुई अधिकरण की कार्रवाई के संबंध में अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रकाशनों, प्रसारणों और नोटिस आदि के संबंध में दिनांक 14 मई, 2009 को साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त शपथपत्र प्रस्तुत किया। इस शपथपत्र को प्रदर्श एस0डब्ल्यू0-34/जे0जे0 (समेकित रूप में) पर मार्क किया गया।

62. इसके बाद एस0डब्ल्यू0-35, मिस्टर दिगान्ता बराह, पुलिस अधीक्षक, जिला तिनसुकिया, असम अपने शपथपत्र जो अनुलग्नकों सहित प्रदर्श एस0डब्ल्यू0-35/के0के0 (समेकित रूप में) पर प्रदर्शित हैं, की यथातथ्यता के बारे में बयान देने के लिए विटनेस बॉक्स में उपस्थित हुए। गवाह ने कहा कि उल्फा का लक्ष्य एवं उद्देश्य हिंसा के माध्यम से असम को भारत संघ से अलग करने के लिए भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना था। उन्होंने कहा कि उनके जिले में उल्फा बहुत ज्यादा सक्रिय था और बड़े पैमाने पर अपहरण, अवैध वसूली एवं निर्दोष व्यक्तियों की हत्याओं में सक्रिय था और इस प्रकार से आम जनमानस में भय का माहौल बना रहा था। गवाह ने अपने जिले में हुए बम विस्फोटों के बारे में भी गवाही दी। गवाहों के बयानों से यह सुस्पष्ट हो जाता है कि उक्त बम विस्फोटों में उल्फा का ही हाथ था। उन्होंने बयान दिया कि उल्फा के भारत के अन्य प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों जैसे कि कामतापुर लिबरेशन आर्गेनाइजेशन (के0एल0ओ0), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (एन0एस0सी0एन0) तथा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैण्ड (एन0 डी0 एफ0बी0) के साथ सक्रिय संबंध थे तथा पश्चिमी पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में आई0एस0आई0 के साथ और अफगानिस्तान में आतंकवादी संगठनों के साथ भी इसके संबंध थे। उन्होंने अपने शपथपत्र एवं गवाही में उल्फा कैडरों में कट्टर आतंकवादियों की गतिविधियों का उल्लेख किया है।

63. एस0डब्ल्यू0-36, मिस्टर वीर विक्रम गोगोई, अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), जिला गोलाघाट, असम ने दिनांक 19 फरवरी, 2009 को प्रदर्श एस0डब्ल्यू0-36/एल0एल0 (समेकित रूप में) सहित अपना साक्ष्य शपथपत्र प्रस्तुत किया और बयान दिया कि उल्फा का लक्ष्य एवं उद्देश्य असम राज्य को भारत से अलग करना था। गवाह ने उल्फा द्वारा अपने जिले में किए जा रहे अपराधों की प्रवृत्ति के बारे में भी बयान दिया जैसे कि अवैध धन वसूली, हत्या, अपहरण तथा विस्फोटकों के प्रयोग से ध्वंसन आदि। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने शपथपत्र में छह ऐसे मामलों को प्रस्तुत किया है जो यह स्पष्ट करते हैं कि उल्फा, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने में शामिल था, लेकिन उक्त मामले दृष्टान्त थे न कि सुविस्तृत। उन्होंने यह भी बयान दिया कि हत्याएं, अवैध वसूली तथा बम विस्फोट आदि निर्बाध रूप से जारी थे। उन्होंने बताया कि उल्फा और देश के अन्य प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों, जैसे कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (एन0एस0सी0एन0) के दोनों गुट, तथा नेशनल

डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैण्ड (एन0डी0एफ0बी0), के बीच सक्रिय संबंध हैं तथा कार्बी-लोन्गरी नॉर्थ कछार हिल्स लिबरेशन फ्रंट (के0एल0एन0एल0एफ0) जैसे अप्रतिबंधित संगठनों के साथ भी संबंध है। गवाह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए उल्फा के विभिन्न काडरों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं से पुख्ता सबूत मिलते हैं कि उल्फा के संबंध विदेशी ताकतों एवं संगठनों से थे जैसे कि पाकिस्तान इंटर सर्विस इंटेलिजेन्स (आई0एस0आई0) तथा पश्चिमी पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से संचालित हूजी आदि जैसे अन्य जेहादी संगठन।

64. एस0डब्ल्यू0-37, मिस्टर आर0आर0 झा, निदेशक, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली, अनुलग्नकों सहित अपने हस्ताक्षरयुक्त शपथपत्र के साथ गवाही देने के लिए उपस्थित हुए। उन्होंने बयान दिया कि प्रदर्श एस0डब्ल्यू-37/एम0एम0 (समेकित रूप में) पर प्रदर्शित शपथपत्र और अनुलग्नकों को उनके साक्ष्य के रूप में पढ़ा जाए। उन्होंने यह गवाही भी दी कि दिनांक 24 फरवरी, 2009 को शपथपत्र दायर करने के बाद भी उल्फा की विधिविरुद्ध एवं गैर-कानूनी गतिविधियां असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैण्ड राज्यों में जारी थीं। वर्ष 2006, 2007 तथा 2008 के दौरान उल्फा द्वारा कारित मुख्य घटनाओं का विवरण उनके शपथपत्र में तथा उसके साथ लगे अनुलग्नक-III में दिया गया है जिसमें विस्फोट की घटनाओं, हिन्दी भाषी व्यक्तियों पर हमले, सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़, नागरिकों पर हमले/अपहरण, अवैध वसूली की घटनाएं, आगजनी की घटनाएं, उल्फा के स्थापना दिवस अर्थात् 7 अप्रैल, 2008 को उल्फा के झंडे को फहराना, दिनांक 15 अगस्त, 2008 को उल्फा के दो काडरों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज छीनना, दिनांक 15 अगस्त, 2008 (स्वतंत्रता दिवस) पर विस्फोट की घटनाएं शामिल हैं। उन्होंने उल्फा के गैर-कानूनी रूप से वसूली करने के अभियान, विदेशों में भर्ती तथा प्रशिक्षण, विस्फोटकों को चलाने का प्रशिक्षण, जेहादियों तथा आई0एस0आई0 के साथ गठजोड़, डी.जी.एफ.आई. (डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलीजेंस) तथा बांग्लादेश की बी0डी0आर0 जैसी विदेशी आसूचना एजेंसियों के साथ गठजोड़ तथा रॉयल भूटान आर्मी द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशनों के परिदृश्य में उल्फा द्वारा भूटान में नए शिविरों की स्थापना और गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस का बहिष्कार करने के संबंध में उल्फा के आह्वान का भी ब्यौरा दिया।

65. एस0डब्ल्यू0-37, श्री आर0आर0 झा के बयानों को रिकार्ड करने के बाद श्री बलदेव मलिक, अधिवक्ता ने भारत संघ के साक्ष्यों को पूर्ण किया। अतः मेघालय राज्य द्वारा कुल मिलाकर पांच गवाहों के बयान लिए गए, अरुणाचल प्रदेश द्वारा छह गवाहों, असम राज्य द्वारा 25 गवाहों के बयान लिए गए तथा केन्द्र सरकार की ओर से एक गवाह का बयान लिया गया जिन्होंने केन्द्र सरकार की ओर से साक्ष्य के माध्यम से एक महत्वपूर्ण शपथपत्र दायर किया। उपरोक्त सभी गवाह प्रासंगिक अभिलेखों के साथ प्रति-परीक्षा के लिए उपलब्ध थे लेकिन उल्फा को नोटिस दिए जाने तथा शिलांग, गुवाहाटी एवं नई दिल्ली में अधिकरण की कार्रवाई संबंधी व्यापक प्रचार प्रसार करने के बावजूद भी किसी भी स्तर पर उल्फा का कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। एक बार फिर अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद जनता में से कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शपथपत्र या साक्ष्य लेकर उपस्थित नहीं हुआ।

66. मामले की सुनवाई 19 मई, 2009 - अर्थात् जिस दिन भारत संघ तथा असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश ने अपनी-अपनी ओर से पक्ष रखे - को होनी तय हुई थी। इस बार भी अधिकरण के समक्ष न तो उल्फा का कोई प्रतिनिधि उपस्थित हुआ और न ही आम जनता की ओर से कोई व्यक्ति।

67. रिकार्ड में दर्ज साक्ष्यों के मूल्यांकन से यह स्पष्ट होता है कि मार्क्सवादी तथा माओ-लेनिनवादी मत के अनुसरण में दिनांक 07 अप्रैल, 1979 को शिवसागर जिले के ऐतिहासिक रोन्ग्र मैदान में अस्तित्व में आए उल्फा की विचारधारा, असम को एक स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित करना था। उल्फा ने एक क्रांतिकारी राजनीतिक दल होते हुए सशस्त्र विद्रोह का तरीका अपनाया। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उल्फा ने अपना झंडा, चिह्न अपनाया तथा स्वयं की अवसंरचना उपलब्ध करवाई जिसमें अपनी केन्द्रीय कार्यकारिणी सभा तथा न्यायपालिका विभाग शामिल है। यहां तक कि उल्फा के संविधान में विदेश सचिव और थल सेनाध्यक्ष की नियुक्ति का भी प्रावधान है।

68. साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट होता है कि उल्फा अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैण्ड सहित सम्पूर्ण ब्रह्मपुत्र घाटी में जोर-शोर से सक्रिय है। हाल ही में इसने मेघालय के पूर्वी एवं पश्चिमी गारो हिल्स - जिसका उपयोग उल्फा द्वाारा आमतौर पर शस्त्रों एवं विस्फोटक सामग्री के लाने ले जाने के लिए किया जाता था - में अपनी गतिविधियों में वृद्धि

की है। अरुणाचल प्रदेश में लोहित, चांगलाँग तथा तीरप जिलों - जिसका उपयोग उल्फा द्वारा आमतौर पर म्यांमार से घुसपैठ करने या म्यांमार में भाग जाने के लिए किया जाता था जहां इनका 28 बटालियनों वाला बेस कैम्प स्थित है- में भी इसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। एस0डब्ल्यू0-6 श्री एस0के0 रॉय, संयुक्त सचिव, गृह और राजनीतिक विभाग, असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी तथा एस0डब्ल्यू0-37, मिस्टर आर0आर0 झा, निदेशक, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली सहित कई गवाहों ने उल्फा द्वारा विशेष रूप से वर्ष 2006, 2007 तथा 2008 में कारित मुख्य घटनाओं तथा जिन क्षेत्रों में घटनाएं हुई हैं आदि के विवरण की तालिका के संबंध में बयान दिए हैं।

69. गवाहों ने एक स्वर में उल्फा द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे क्रूरतम तरीकों के बारे में बयान दिया है जिसमें बम विस्फोट, हत्याएं तथा अवैध वसूली और संगठन द्वारा दहशत का माहौल बनाना शामिल है जिसके कारण बहुत से फिरौती पीड़ितों को पुलिस को सूचित किए बिना इस संगठन को बड़ी मात्रा में धनराशि देने के लिए विवश होना पड़ता है। यह रिकार्ड में है कि बड़े पैमाने पर उल्फा द्वारा अवैध वसूली से करोड़ों रुपये जमा किए गए हैं जिनका उपयोग संगठनात्मक तंत्र, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा शस्त्रों के प्रापण आदि के वित्तपोषण के लिए किया जा रहा है।

70. यह स्पष्ट है कि शुरूआत में इस संगठन को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत दिनांक 27 नवम्बर, 1990 से 'विधिविरुद्ध संगठन' घोषित किया गया था तथा इसके बाद उल्फा को 'विधिविरुद्ध संगठन' घोषित करने वाली अधिसूचना की वैद्यता में समय-समय पर विस्तार किया गया। रिकार्ड से यह भी पता चलता है कि समय-समय पर प्रतिबंध संबंधी अधिसूचना की वैद्यता अवधि में विस्तार किए जाने के बावजूद भी उल्फा की आपराधिक गतिविधियां निर्बाध रूप से जारी रहीं। वास्तविकता यह है कि दिनांक 1 जनवरी, 2006 से 15 अक्टूबर, 2008 के दौरान उल्फा ने 560 हिंसक घटनाओं तथा सुरक्षा बलों के 29 कर्मिकों सहित 346 व्यक्तियों की हत्या को अंजाम दिया है। हाल ही की रिपोर्ट दर्शाती है कि दिनांक 30 अक्टूबर, 2008 को निचले असम के विभिन्न जिलों में हुए 9 शृंखलाबद्ध विस्फोटों जिनमें 76 व्यक्तियों की मौत हुई थी तथा 351 से अधिक घायल हुए थे, में उल्फा का हाथ था।

71. उल्फा की विधिविरुद्ध एवं अवैध क्रियाकलापों के विरुद्ध गवाही देने वाले गवाहों द्वारा अधिकरण के समक्ष दिए गए बयानों के साथ-साथ उनके शपथपत्रों के समग्र अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उल्फा की गैर-कानूनी एवं हिंसक गतिविधियों का उद्देश्य असम की आजादी के लक्ष्य को पाने के साथ-साथ भारत की संप्रभुता और भौगोलिक एकता को हानि पहुंचाना था। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि उक्त उद्देश्य के लिए उल्फा, जो एक क्रांतिकारी दल है, ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य विधिविरुद्ध एवं प्रतिबंधित संगठनों के साथ गठजोड़ स्थापित किया और प्रतिबंध की अवधि के दौरान भी असम को भारत से अलग करने के लिए कई विधिविरुद्ध एवं हिंसक कार्रवाइयों में शामिल रहा, जिसमें बड़े पैमाने पर जबरन वसूली, हत्याएं तथा फिरोती के लिए अपहरण शामिल हैं। रिकार्डों से यह भी पूर्णतः स्पष्ट है कि इसने भारत की संप्रभुता एवं राष्ट्रीय एकता के लिए घातक ताकतों के साथ मिलकर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का खुला प्रचार करने के लिए पड़ोसी देशों विशेषतः अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अपने शरणस्थल और प्रशिक्षण शिविर स्थापित कर लिए हैं।

72. हाल ही में, जैसा कि गवाहों के साक्ष्यों से स्पष्ट है कि संगठन ने अलगाववादी, विघटनकारी तथा हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अपने काइरों को प्रेरित किया है और आम नागरिकों, विशेषतः व्यापारी वर्ग, की हत्या कर रहा है तथा पुलिस एवं सुरक्षा बलों के कार्मिकों को अपना निशाना बना रहा है। दस्तावेजों में यह भी विदित होता है कि उल्फा, सीमापार से बड़ी संख्या में अवैध शस्त्र एवं गोलाबारूद प्राप्त कर रहा है/घुसपैठ करवा रहा है, जिसके लिए यह जनता से जबरन वसूली तथा अवैध करों के रूप में बड़ी मात्रा में धनराशि उगाह रहा है। अलगाववादी गतिविधियों के विस्तार के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के नौजवानों को अपने काइरों में शामिल होने का लालच दे रहा है जबकि आम जनता इसकी हिंसक गतिविधियों के कारण भय के माहौल में जीवन यापन कर रही है।

73. यह भी महत्वपूर्ण है कि गवाहों ने इस बात को ध्यान में रखते हुए, कि घटनाओं का ब्यौरा विशेष शाखा तथा असम के पुलिस मुख्यालय से लेकर असम सरकार के पास अग्रेषित हो चुका है, एकजुट होकर यह कहा कि अब उल्फा की गतिविधियां दस्तावेजों में पूरी तरह मौजूद हैं। इसने लगभग

सभी गवाहों को पूछताछ संबंधी बयान, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता स्वीकार करने संबंधी बयान सहित रिकार्ड पर विभिन्न प्रथम सूचना रिपोर्ट, गवाहों के बयान, जब्त की गई वस्तुओं की सूची, मांग पत्रों की प्रतियां, जबरन वसूली के नोटिस तथा अभियुक्त व्यक्तियों के बयानों को सिद्ध करने में सक्षम बनाया।

74. गवाहों ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि असम को भारत से अलग करने के लिए उत्फा के लिबरेशन ऑफ ए'चिक इलाइट फोर्स (एल.ए.ई.एफ.), पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (पी.एल.एफ.), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैण्ड (एन.डी.एफ.बी.), हरकत-उल-मुजाहिदीन (एच.यू.एम.), हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी (एच.यू.जी.आई.), ए'चिक नेशनल वालियंटियर्स काउंसिल (ए.एन.वी.सी.), कामतापुर लिबरेशन आर्गेनाइजेशन (के.एल.ओ.), त्रिपुरा पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (इसाक मुईवाह) (एन.एस.सी.एन.-आई.एम.), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (खापलंग) (एन.एस.सी.एन.-के), कार्बी-लोगरी नॉर्थ कछार हिल्स लिबरेशन फ्रंट (के.एल.एन.एल.एफ.), ऑल त्रिपुरा टाईगर फोर्स (ए0टी0टी0एफ0), पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर (पी0एल0ए0), झारखंड के माओवादी, पश्चिमी पाकिस्तान और बांग्लादेश में आई0एस0आई0, बांग्लादेश के डी0जी0एफ0आई0 तथा लिबरेशन टाईगर्स ऑफ तमिल इलम (लिट्टे) के साथ संचालनात्मक संपर्क हैं। उत्फा के काडरों को उनके विशेषज्ञों के अलावा पाकिस्तानी आसूचना एजेंसी, इंटर सर्विसिज इंटेलिजेन्स (आई0एस0आई0) द्वारा भी प्रशिक्षण दिया जाता है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उत्फा के शीर्ष नेता बांग्लादेश में शरण ले रहे हैं जहां पर प्रशिक्षण शिविर भी स्थापित हैं। रिकार्ड में यह भी विदित है कि कुछ काडर भूटान और म्यांमार में भी शरण ले रहे हैं तथा असम राज्य का प्रयोग विदेशों के लिए एक गलियारे के रूप में किया जा रहा है। जैसा कि उल्लिखित गवाहों के साक्ष्य में बताया गया है असम, मेघालय तथा अरुणाचल प्रदेश के कुछेक जिलों का प्रयोग भूमिगत होने के लिए किया जा रहा है।

75. असम, मेघालय तथा अरुणाचल प्रदेश की सरकारों के साथ-साथ भारत संघ द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का अब तक इस अधिकरण के समक्ष खण्डन नहीं हुआ है क्योंकि न तो उल्फा ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है और न ही उसके द्वारा कोई अभ्यावेदन दायर किया गया है।

76. इस संगठन को भारत की सुरक्षा के प्रति घातक विदेशी शक्तियों से गठजोड़ करके खुलेआम राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल होने से रोकने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सभी गवाहों ने एक स्वर में उल्फा को विधिविरुद्ध संगठन घोषित करने संबंधी घोषणा को जारी रखने का अनुरोध किया है। गवाहों ने कहा कि उल्फा की गतिविधियों पर काबू पाना समय की ज्वलंत मांग है क्योंकि उल्फा द्वारा की जा रही हिंसा की गूंज पूरे राज्य में महसूस की जा रही है तथा इसका मुख्य निशाना अर्थात् हिन्दी भाषी जनसंख्या, पुलिस तथा सुरक्षा कार्मिक, और व्यापारी वर्ग स्थायी रूप से भय के साये में जीते हुए इसकी गतिविधियों के आघात को झेल रहे हैं।

77. मामले को तथा इस बात, कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 का उद्देश्य भारत की एकता एवं संप्रभुता के विरुद्ध की जाने वाली गतिविधियों से निपटने के लिए शक्तियां उपलब्ध कराना है, को ध्यान में रखते हुए इस अधिकरण का यह मत है कि केन्द्र सरकार द्वारा इस निर्णय पर पहुंचना पूर्णतः उचित था कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में दी गई परिभाषा के अनुसार उल्फा एक 'विधिविरुद्ध संगठन' है क्योंकि उल्फा की गतिविधियां भारत की संप्रभुता एवं एकता के लिए खतरा हैं। उल्फा की विधिविरुद्ध एवं हिंसक गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा इसके अवैध लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति में इसके काडरों की पुनः लामबंदी को रोकने के लिए तथा विगत में प्रतिबंध संबंधी आदेशों के बावजूद इस संगठन से होने वाले संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए उल्फा को, उसके सभी गुटों, शाखाओं तथा अग्रणी संगठनों सहित *तत्काल प्रभाव से* विधिविरुद्ध संगठन घोषित करने का केन्द्र सरकार का निर्णय भी पूर्णतः उचित प्रतीत होता है। तदनुसार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा दिनांक 27.11.2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 2746(अ) में

की गई घोषणा को संपुष्ट किया जाना उचित है और एतद्वारा उक्त अधिसूचना की संपुष्टि की घोषणा की जाती है।

संदर्भ का उत्तर ऊपर उल्लिखित शर्तों के अधधीन दे दिया गया है।

हस्ता/-

न्यायविद रेवा खेत्रपाल

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण

दिनांक 22 मई, 2009

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th June, 2009

S.O. 1506(E).—In terms of section 4(4) of the Unlawful activities (Prevention) Act, 1967, the order of the Tribunal presided over by Hon'ble Justice Reva Khetrpal, Judge, Delhi High Court, to whom a reference was made under Section 4(1) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the United Liberation Front of Asom (ULFA) of Assam as unlawful is published for general information:

[No. 11011/55/2008-NE. III]

NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

REPORT OF THE TRIBUNAL

**REPORT OF THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION)
TRIBUNAL CONSISTING OF HON'BLE MS. JUSTICE REVA
KHETRAPAL, JUDGE, DELHI HIGH COURT**

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the 'Act'), the Central Government has declared the United Liberation Front of Asom as 'Unlawful Association' vide Notification No.

S.O. 2746(E) dated 27.11.2008.

2. The Central Government has opined vide its notification no. 2746 dated 27.11.2008 that ULFA has continued to:-

- (i) indulge in various illegal and violent activities intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India in furtherance of its objective of liberating Assam;
- (ii) align itself with other unlawful associations of North Eastern Region to secede Assam from India;
- (iii) in pursuance of its aims and objectives, engaged in several unlawful and violent activities during the currency of its declaration as an unlawful association;
- (iv) procure and induct more illegal arms and ammunitions from across the border;
- (v) extort and collect huge funds and illegal taxes from the public for its unlawful activities.

3. A look at its Constitution shows that the United Liberation Front of Asom (hereinafter referred to as the 'ULFA') and the various wings thereof was formed on 7th April, 1979 with the avowed objective of "liberation of Assam" from the Indian Union through an armed struggle. The outfit allegedly continues to pursue this objective in alliance with other armed secessionist organisations of the North East Region, and was initially declared as an 'unlawful association' under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 with effect from the 27th November, 1990 for professing the:

- (i) aim of liberating Assam from India;
 - (ii) for indulging in various illegal and violent activities with a view to disrupt the sovereignty and integrity of India and to create a deep sense of insecurity among the people;
 - (iii) for extorting money, committing murder of political leaders, police officials, businessmen and others;
 - (iv) indulging in threats, intimidation, kidnapping of people, snatching of fire arms from license holders, dacoities, highway robberies and looting of banks, forcible occupation of lands and buildings.
4. The notification dated 27th November, 1990 declaring ULFA as 'unlawful association' was extended from time to time and at present the notification by which this outfit has been declared an 'unlawful association' under the Unlawful Activities (Prevention) Act 1967 is valid upto the 26th November 2008. This outfit is also declared as a 'terrorist organisation' under Section 35 of the aforesaid Act.
5. Since 1991 and upto 15th October, 2008, the ULFA is alleged to have been responsible for the killing of 1984 persons including 368 police personnel. During the year 2008 (upto 15th October, 2008), it is stated, the ULFA cadres have killed 43 persons including 3 personnel of security forces in 117 incidents of violence, and have been responsible for the killing of 185 persons including 7 personnel of security forces, in 201 incidents during the

corresponding period of 2007. During 2007, the killing by ULFA had reached an all time high with 12.4 per cent increase in violent incidents and 83.3 percent increase in killing as compared to the previous year. Recent reports indicate that ULFA was involved in the nine serial blasts in different districts of Lower Assam on 30th Oct' 08 which resulted in the killing of 76 persons and injured over 351 persons though ULFA has denied their involvement in these blasts.

6. In view of the aforesaid, the Central Government has opined that it is necessary to declare the ULFA as an 'unlawful association' under the Act for a further period of two years; and that there should not be any gap between the date on which the declaration of this outfit as 'an unlawful association' expires and the fresh date for declaration of this outfit as 'an unlawful association', as any delay would give undue advantage to the outfit. It was, therefore, deemed necessary to declare this outfit as 'unlawful association' with immediate effect from 27th November, 2008 under the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

7. Exercising powers conferred by sub-Section (1) of Section 5 of the Act, the Ministry of Home Affairs, Government of India, vide its subsequent Notification No. S.O.2943(E) dated 19th December 2008, constituted this Tribunal for the purpose of adjudicating whether or not there was sufficient cause for declaring the ULFA of Assam as unlawful association and made reference to this Tribunal through Mr. R.R Jha, Director(NF.H) vide Reference

No. 11011/55/2008-NE.III dated 23rd December, 2008, under the provisions of Section 4 (1) of the Act.

8. The Reference was received by this Tribunal on 23rd December, 2008.

9. Having received the Reference, vide order dated 23rd December, 2008 this Tribunal listed the Reference for preliminary hearing on 12th January, 2009.

10. On consideration of the Reference and the material placed on record by the Central Government, in pursuance of the provisions of sub-section (2) of Section 4 of the Act, this Tribunal by its order dated 12.01.2009 issued notice to the ULFA, through the Chief Secretary of the respective States, to show cause in writing within 30 days from the date of the service of such notice, why the ULFA should not be declared an unlawful association. By the said order, this Tribunal further directed that the notice shall be served on the aforesaid Association on the addresses as may be available by publication in two daily National and two local newspapers published in the locality where the ULFA has its establishments or its presence is known in the State of Assam and outside, as well as in the electronic and print media and also by affixing a copy thereof to some conspicuous parts of the office, if any, of the said Association, and by serving a copy of such notice, where possible, on the principal office bearers, if any, of the Association at their addresses by registered post or otherwise. The proclamation about the contents of the notice was also ordered to be made by beat of drum as well as by means of

loudspeakers in areas where the activities of the said Association are ordinarily carried on. It was additionally directed that the notice should also be served by pasting the said notice on the Notice Board of the office of each District Magistrate/Tehsildar at the Headquarters of the District or Tehsil and the office of the Deputy Commissioner and at market places, as feasible.

11. In order to ascertain the position of service and for further proceedings, the matter was directed to be listed on 27th February, 2009. In the meanwhile, the Central Government and the Governments of Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Nagaland were ordered to submit their affidavits and documents in support of the grounds on which the aforesaid Association was liable to be declared unlawful.

12. Affidavits of service were filed by Shri R.R. Jha, Director to the Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi; Shri S.K. Roy, Joint Secretary to the Government of Assam, Political (A) Department, Assam Secretariat, Dispur, Guwahati; Dr. Shreeranjana, Commissioner and Secretary to the Government of Meghalaya, Political Department, Shillong, Meghalaya; Mr. Avinash Kumar Mishra, Principal Resident Commissioner, Government of Arunachal Pradesh and Ms. Khrienuo Metha, Joint Resident Commissioner to the Government of Nagaland.

13. In the affidavit of service filed by Shri R.R. Jha, Director to the Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi it is stated that pursuant to the order dated 12.01.2009, the Government of Assam and the

Government of Meghalaya had taken all effective steps for effective service of notice.

14. The affidavit of service of Shri S.K. Roy, Joint Secretary to the Government of Assam, Political (A) Department, Assam Secretariat, Dispur, Guwahati dated 17th February, 2009 states that the notice issued by this Tribunal was published in the local Hindi newspaper “Prata Khabar” on 28.01.2009, and the vernacular major Assamese newspapers “Dainik Janambhumi” on 13.02.2009, “Ajir Dainik Batori” on 13.02.2009 and “Amar Asom” on 28.01.2009. Copies of the newspaper clippings were filed with the affidavit. The notice was also stated to have been broadcast and telecast from the Doordarshan Kendra in the Evening Regional News on 28.01.2009 and the original confirmation letter issued by the Doordarshan Kendra, Guwahati was filed with the affidavit. The notice was also stated to have been served by beat of drum and announcement through loudspeakers in conspicuous places, haats and bazaars and also by pasting of the notice at the office of the District Magistrate/Tehsildar and at the Police Station. Apart from this, the notice was also stated to have been served on the family members of known ULFA activists in the presence of independent witnesses. Such an exercise was stated to have been carried out in 23 Districts of Assam where the aforesaid unlawful organisation (ULFA) has been carrying on its activities, namely, Nagaon, Sonitpur, Morigaon, Guwahati City, Goalpara, Nalbari, Jorhat, Dhemaji,

Darrang, Sivasagar, Tinsukia, Dibrugarh, Karbi Anglong, Bongaigaon, Kokrajhar, Golaghat, Barpeta, Dhubri, Udalguri, Lakhimpur, Chirang, Kamrup and Baksa. Copies of the letters mentioning service of notice on ULFA sent by the respective Superintendents of Police of the above-mentioned Districts were filed with the affidavit.

15. In the affidavit of service filed by Dr. Shreeranjana, Commissioner and Secretary to the Government of Meghalaya, Political Department, Shillong, Meghalaya it is stated that pursuant to the order dated 12.01.2009 passed by this Tribunal, the issuance of show cause notice to the ULFA under sub-section (2) of Section 4 of the Act, 1967 was given wide publicity, both in the electronic and print media, especially in the Districts of the State of Meghalaya, where the ULFA is very active. It is further stated that the notice was published in several newspapers including the National English newspaper "The Indian Express" on 12th February, 2009 (Annexure-'A-1'), the local English newspaper "Shillong Times" on 12th February, 2009 (Annexure-'A-2'), the vernacular newspaper "Salantini Janera" on 12th February, 2009 (Annexure-'A-3') and another local newspaper "U Nongsain Hima" on 12th February, 2009 (Annexure-'A-4'). The contents of the notifications/notices were also broadcast on 12th February, 2009 evening in Khasi, Garo and Jaintia bulletins and telecast through the Shillong Station of All India Radio and

through the Doordarshan Kendra, Shillong at 6.30 p.m. on 11.02.2009

(Annexure-'A-5'). Additionally, it is stated that the notifications/notices had also been hung on the notice board of the Deputy Commissioner's office in the West Garo Hills District, the East Garo Hills District and West Khasi Hills District of the State (Annexure-'A-6').

16. An affidavit of service was also filed by Shri Avinash Kumar Mishra, Principal Resident Commissioner, Government of Arunachal Pradesh dated 22nd March, 2009, stating that the service of the show cause notice issued by this Tribunal on 12.01.2009 was complete, having been published in the National English newspaper "Times of India", Guwahati Edition, in its publication dated 03.03.2009, "The Telegraph Newspaper", Guwahati Edition, in its publication on 05.03.2009, "The Arunachal Times" newspaper in its publication on 07.02.2009 and in the daily newspaper "Arunachal Front" in its publication on 07.02.2009. It is further stated that the show cause notice was telecast on all local channels of the cable network from 13.02.2009 to 07.03.2009 as confirmed by the Manager of the local cable network on 06.03.2009 and was broadcast on AIR Itanagar on 03.03.2009 and 04.03.2009 in English and Hindi at 6.00 pm. as confirmed by the Programme Executive of All India Radio, Itanagar on 05.03.2009. The news item in this regard was also telecast on the North-East news of the Doordarshan Kendra on 18.02.2009

at 7.15 p.m. and confirmation in this regard was received on 19.02.2009 from the Head of Office, Doordarshan Kendra, Itanagar. The Deputy Commissioner of Tirap District, Khonsa on 05.03.2009, the Deputy Commissioner, Changlang District on 04.03.2009, the Deputy Commissioner, Lohit District, Tezu on 04.03.2009 and the Deputy Commissioner, Lower Debang Valley District on 05.03.2009, confirmed that the notification and the show cause notice had been affixed on the notice boards in the entire District and announcements had been made through the public address system in all circles of the District. The Deputy Commissioners of the various Districts also confirmed service of notice.

17. An affidavit of service was also filed by Ms. Khrienuo Metha, Joint Resident Commissioner to the Government of Nagaland dated 26th March, 2009 to the effect that pursuant to the orders passed by this Tribunal, the issuance of show cause notice to ULFA was given wide publicity both in the electronic and print media. Copies of newspaper clippings containing the notice in the “Nagaland Post” Daily Newspaper Edition dated 19.03.2009, the “Eastern Mirror” Daily Newspaper Edition dated 19.03.2009 and the “Morung Express” Daily Newspaper Edition dated 19.03.2009 were annexed with the affidavit. It was also stated that the contents of the notice had been broadcast through the Kohima Station of All India Radio and had also been telecast

through the Doordarshan Kendra, Kohima. The notice had also been displayed on the notice boards of the Deputy Commissioner's office of various Districts in the State.

18. In the aforesaid manner, notices were duly served on the ULFA in the States of Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Nagaland. However, no objections/replies/written statements were filed by or on behalf of the ULFA within the stipulated period of 30 days from the date of the service of the notice or even after the said period. There was also no appearance on behalf of the ULFA either in person or through counsel. However, an unsigned letter was received from one Shri Ghanshyam Deka dated 04.02.2009 to the effect that he was a member of the United Liberation Front of Assam (ULFA), but had returned to the mainstream before the administration on 01.11.2007 and in view thereof, he was not the right person to give any comment over the notification referred to in the notice.

19. The Governments of Assam, Meghalaya and Arunachal Pradesh led evidence by way of affidavits supported with documents.

20. Hearing was held by the Tribunal in the first instance at Shillong, Hotel Pinewood on 26th and 27th April, 2009, where at the outset, Dr. Shreeranjana, Commissioner & Secretary, Government of Meghalaya, Political Department, Shillong placed on record the extracts of the daily newspapers, viz., the

“Mawphor” dated 20th April, 2009, the “Meghalaya Guardian” dated 28th April, 2009 and the “Salantini Janera”, Tura Mangolbar dated April 21, 2009 evidencing issuance of public notice that the Tribunal would be recording the evidence of the States of Meghalaya, Arunachal Pradesh and Assam on the 26th and 27th of April, 2009 at 10.30 a.m. Dr. Shreerajan also placed on record the confirmation received from the Prasar Bharti Broadcasting Corporation of India, Doordarshan Kendra, Lathkore Peak, Shillong (Meghalaya) with regard to the broadcasting of the hearing of the Tribunal, as a news format, during their news based programme “City Scan” in Khasi and in English, on 18.04.2009 (Saturday) evening.

21. As per the evidence of SW-1, Dr. Shreerajan, who tendered in evidence his affidavit along with Annexure A-1 to A-11 exhibited as Exhibit SW-1/A (collectively), predominantly the problem in Meghalaya in respect of the illegal and unlawful activities of ULFA is in the East Garo Hills and in the West Garo Hills. The ULFA, the witness stated, was primarily engaged in the illegal and unlawful activities of kidnapping, extortion, demand for ransom, use and possession of illegal arms and ammunitions and killing of innocent persons. The ULFA also had linkages with certain groups in Bangladesh carrying on illegal and unlawful activities; and the East and West Garo Hills were being used as transit points for illegal immigration from Bangladesh into

India. The aims and objectives of ULFA were anti-National, being to secede from the country. The propaganda spread by them was that India is in illegal occupation of their territory. The main targets of ULFA were the armed forces and the members of the executive, apart from innocent persons. Their activities which were earlier by and large covert had as of today become more overt. Several ULFA cadres had been apprehended along with arms and ammunitions, as depicted in Annexures A-7, A-8, A-9 and A-10 (collectively) to the Affidavit. Certain groups of ULFA had even surrendered to the Meghalaya Government. On 28.08.2008, some ULFA cadres had served a demand notice on Shri Surjya Kumar Gogoi, Branch Manager, State Bank of India at Resubelpara, East Garo Hills District demanding a sum of Rs.5,00,000/- (Rupees Five Lakhs only). The said demand note was appended as Annexure A-11 with his affidavit. The ULFA, according to the witness, had links with other militant organisations, such as Liberation of A'chik Elite Force (LAEF) and People's Liberation Front (PLF). The ban with regard to their illegal activities was necessary as they were now operating openly in the East and West Garo Hills. In case their activities were not banned, he stated, it could result in irreparable damage to the integrity of the country.

22. SW-2, Mr. D. Vijay Kumar, District Magistrate of East Garo Hills District deposed that the ULFA was very active in the East Garo Hills District

and that its illegal activities, which had started in the District in the year 2007, had increased in the year 2008. He stated that the ULFA maintained links with many other illegal organisations and had active links with the National Socialist Council of Nagaland (Isak-Muivah) (NSCN-IM), Liberation of A'chik Elite Force (LAEF), People's Liberation Front (PLF) and A'chik National Volunteers Council (ANVC). The witness also corroborated the statement of SW-1, Dr. Shreeranjana with regard to the aims and objectives of ULFA, the nature of the unlawful activities being carried on by the ULFA and the fact that the East Garo Hills District was being used as the transit point for the illegal immigration of Bangladeshi nationals into Indian territory. The witness tendered in evidence his affidavit with its enclosures, being Annexure-I to Annexure-VI, exhibited as Exhibit SW-2/B (collectively), proving on record copies of FIRs and Seizure Memos in respect of the incidents alleged to have taken place in the East Garo Hills District on various dates as well as a chart as furnished by the Superintendent of Police, East Garo Hills District, containing the extracts of Police records corresponding to the criminal cases mentioned in the affidavit of the witness.

23. SW-3, Mr. Sylvester Nongtnger, Superintendent of Police, East Garo Hills, Williamnagar deposed that affidavit dated 21st February, 2009 was sworn by him and that he tendered in evidence the said affidavit with Annexures I to

VI as Exhibit SW-3/C (Collectively). The said Annexures comprised of copies of the FIRs and Seizure Memos relating to the various cases registered against the ULFA. A chart of cases pending against the ULFA was also tendered in evidence. The witness submitted that the main targets of the organisation were the Government officials, including the Police personnel, and the members of the business community. The main supporter of the organisation was the National Socialist Council of Nagaland (Isak-Muivah) (NSCN-IM). Arms training and supply was the main help rendered by this organisation. The ULFA also had active links with the A'chik National Volunteers Council (ANVC) and the Liberation of A'chik Elite Force (LAEF). He stated that recently one of the ULFA members, named Palling Hatho, had surrendered with his M-20 pistol to the Government of Meghalaya.

24. SW-4, Mr. F.R. Kharkongor, Deputy Commissioner, West Garo Hills District, Tura, Meghalaya tendered in evidence his affidavit dated 24th April, 2009 Exhibit SW-4/1, and stated that he had also gone through the affidavit of SW-5 Shri J.F.K. Marak, Superintendent of Police, West Garo Hills District, Tura and the annexures filed alongwith the same and that he fully endorsed the same.

25. SW-5 Mr. J.F.K. Marak, Superintendent of Police, West Garo Hills District, Tura, Meghalaya, tendered in evidence his affidavit dated 21st

February, 2009 with the enclosures, being Annexures-A to S, as Exhibit SW-5/D (collectively) and deposed with regard to the various unlawful activities carried on by the ULFA within his District, stating that its cadres were very active in his District, especially in the entire Assam-Meghalaya border belt under his jurisdiction. He stated that the ULFA was actively supporting the nascent militant groups of Garo Hills, like the People's Liberation Front of Meghalaya (PLF-M) and the Liberation of A'chik Elite Force (LAEF) by supplying arms and ammunitions and imparting training to the cadres of these outfits, which posed a serious threat to the security of the State in general and the District in particular. He further stated that the criminal activities of ULFA in the West Garo Hills included crimes like extortion, kidnapping, murder, carrying of illegal arms and ammunitions in sizeable quantity and for the aforesaid purpose, the ULFA cadres were making their best efforts to recruit local youth in their cadres. He also deposed that the ULFA had nexus with Bangladeshi nationals and was using his District as a corridor for infiltrating into the country and for the members of the ULFA to go to Bangladesh, whenever necessary.

26. SW-6, Mr. Supriya Kumar Roy, Joint Secretary, Home and Political Department, Assam Sachivalaya, Dispur, Guwahati tendered in evidence his affidavit along with its annexures. He stated in his affidavit that despite

successive bans which were being imposed on ULFA, the outfit had been indulging in various unlawful and violent activities with a view to disrupt the peace, sovereignty and integrity of India and to create a deep sense of insecurity among the people. According to him, during the period from November 27, 2006 to November 26, 2008, the ULFA activists had been found involved in a total number of 491 violent incidents in which a total number of 224 persons were killed, 1027 persons were injured and 12 persons were kidnapped for ransom. During the aforesaid specific time frame, the ULFA militants had triggered off 152 bomb/grenade blasts in the State, besides carrying on other subversive activities. In the said incidents of bomb blasts, 82 innocent lives including those of 9 security forces were lost and injuries caused to 966 persons. A certified copy of the detailed chart setting out the aforesaid incidents District-wise, giving figures of those who were killed and injured was submitted by him as Annexure-'B' (Colly.) along with a certified copy of the summary of the major unlawful activities of ULFA, which was submitted as Annexure-'C' to his affidavit.

27. SW-6, Mr. Supriya Kumar Roy in his affidavit further stated that the ULFA was running training camps in Bangladesh and Myanmar, from where they had been operating and implementing guerilla warfare by adopting hit and run tactics in the territory of Assam. Training camps had been established in

the Assam-Arunachal Border areas near Lakhimpur, Dhemaji and Tinsukia districts and in the Assam-Meghalaya Border areas adjoining Kamrup, Goalpara and Karbi Anglong Districts. The ULFA militants were using several clandestine routes for movement to and from Bangladesh and Myanmar. The ULFA leaders staying in Bangladesh had observed the Army Day of the outfit on March 16, 2008 at Paschim Bakakura training camp (Bangladesh) under Jinaighati PS of Sherpur district and in the Motijheel area of Dhaka, and the cadres staying in Boroghazni and Bankakura area had also attended the said function. Paresh Baruah (Commander-in-Chief of ULFA) and Biju Deka had explained the significance of the Army Day of the outfit to the cadres in Bakakura while Raju Barua had read out the speech of Paresh Baruah (C-in-C, ULFA) to the gathering at Motijheel. In 2008, ULFA had also observed its Raising Day (April, 2007) and Army Day (16th March) in the flat of Paresh Baruah (C-in-C, ULFA) in Dhaka, where all ULFA leaders/cadres had attended the programme with their families. Arabinda Rajkhowa, Chairman, ULFA had read out the presidential speech at the function. The aforesaid facts, the witness stated, were divulged by the arrested and surrendered ULFA cadres before the Police. He also stated that the ULFA cadres were still being imparted training by the Pakistani Intelligence Agency, Inter Services Intelligence (ISI) and the Director General of Field Intelligence

(in short "DGFI") of Bangladesh to continue anti-national and terrorist activities in the State of Assam as well as in India. The witness also stated that the unholy nexus of ULFA with Islamic terrorists, the Director General of Field Intelligence (in short "DGFI", an external intelligence organisation of Bangladesh), the Bangladesh Rifles (in short "BDR") and the ISI had added a new dimension to the internal security scenario of the State as well as of entire India. Islamic militants had chalked out a plan to hijack an aircraft from Guwahati with the help of ULFA. The ULFA was also maintaining operational understanding with other insurgent groups of the North East Region, namely, the Kamtapur Liberation Organisation (KLO), the Manipur People's Liberation Front (MPLF) and the Tripura People's Democratic Front (TPDF). Apart from this, the ULFA had been asking the people of Assam to boycott the observance of "Republic Day" (26th January) and "Independence Day" (15th August) in the years 2007 and 2008 and to observe general strike on these two specific days in the State. The use of PTD explosives (Programmable Time Device explosives) was demonstrated by the ULFA during official Independence Day celebrations in Dhemaji in 2004, where 13 persons including 6 students who were minors died. The outfit was also continuing its anti-India and anti-Government propaganda through its fortnightly Newsletter "FREEDOM" circulated through the Internet and

through the media. Also, the ULFA leadership was still deputing cadres to the training camps of Bankakura (Bangladesh) where these cadres were imparted expertise in explosives, viz., PTD (Programmable Time Device), Claymore Device, LAD (Light Activated Device), etc. The survey conducted by the ULFA in Myanmar-China Border for acquisition of sophisticated weaponry and transshipment of the same to the State for subversive activities had further added a new dimension to the internal security scenario in the State. The ULFA leadership had deputed Prabal Neog and Partha Gogoi to survey the area for transshipment of weapons from there. Similarly, the ULFA militants also dispatched arms, ammunition, grenades, explosives, etc. in several batches of small consignments to Assam from Bangladesh through the clandestine routes of the West Garo Hills and the South Garo Hills of Meghalaya. The ULFA activists had been extorting huge amounts of money from various individuals, businessmen, etc. by serving extortion notices on their letter heads during the period of November 27, 2006 to November 26, 2008. Many unserved extortion notes and letter pads were seized or recovered by the Police of different Districts from the ULFA cadres as well as from their hideouts. Significantly, many cases of such looting/extortion by the ULFA had remained unreported to the Police as the aggrieved persons were unwilling to lodge any formal complaint with the Police in apprehension of reprisal by the outfit. The

weapons seized at different points of time clearly showed that the ULFA was in possession of the latest sophisticated upgraded light weaponry, which has given it enhanced striking capabilities. The ULFA leaderships based in Bangladesh had procured sophisticated arms/explosives/ammunition and communication devices from many foreign countries. These procured arms were dispatched to Assam through Meghalaya and the porous border of Myanmar and other safer clandestine routes to continue their subversive activities in Assam. The intelligence reports indicated that the ULFA was making fresh preparations to launch concerted operations against the Army/Police/PMF/Posts/Patrol parties and indulging in targeted killing of common people as well as the Hindi speaking populace of Assam.

28. The witness SW-6, Mr. S.K. Roy also tendered in evidence the Constitution of the ULFA (Annexure-A), a detailed chart of the unlawful activities of ULFA [Annexure-B (Colly.)], a summary of the major unlawful activities of ULFA (Annexure-C), the certified copies of the relevant extracts of interrogation statements of ULFA cadres (i) Prabal Neog, (ii) Ananta Gogoi @ Shasanka Baruah, (iii) Noni Khaklary @ Anup Khaklary and debriefing statements of (iv) Ranjit Kr. Roy Hazong @ Bakul Roy and (v) Mani Saikia @ Bubu Dutta [Annexure-D (Colly.)] and the relevant extracts of the interrogation statement of ULFA cadres Monoj Tamuli @ Rāndip (Annexure-

E), the certified copies of the relevant extracts of the mouthpiece of the outfit “FREEDOM” dated 20.01.2008 [Annexure-F (Colly.)] and the certified copies of extortion letters on letterheads of ULFA with their English translations [Annexure-G (Colly.)].

29. The affidavit of the witness along with all the above enclosures was exhibited as Annexure-6/E (Colly.). Significantly, this witness testified that after the filing of his affidavit dated 27th February, 2009, on 6th April, 2009, a day prior to the Raising Day of ULFA, the ULFA had caused a bomb explosion to take place in the area of Malegaon. The bomb had been fitted into a bicycle which was parked in a thickly populated area and the explosion resulted in the death of 9 persons and injuries to 62 persons, many of whom were grievously injured. About 15 vehicles were also damaged in the course of the explosion.

30. SW-7, Mr. Pradip Chandra Saloi, Senior Superintendent of Police, City Guwahati, in his evidence stated that the affidavit dated 18th February, 2009 was deposed to by him and that the Annexures-1 to 24 to the said affidavit were certified true copies of the documents derived from the official records, exhibited as Exhibit SW-7/F (Colly.). He deposed that in the city of Guwahati and in entire Assam, the ULFA was very active and was indulging in large-scale unlawful activities and was waging war against the State. He underlined

that he had cited only eight cases in his affidavit, out of the innumerable cases which had arisen as a result of the illegal activities of ULFA, by way of evidence. The involvement of ULFA cadres, he testified, was well established and well documented in his State. The ULFA cadres were taking shelter from time to time in different parts of the Guwahati City with a view to commit subversive activities in the City, and there had been a case in which they had been able to catch hold of two ULFA cadres, who had planned to hijack an aircraft from the Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport (formerly Borjhar Airport) to Rawalpindi (Pakistan) or Afghanistan through Bhutan and on interrogation, the two ULFA cadres admitted having planned to commit the aforesaid crime. The witness further stated that the ULFA activists had active linkages with LTTE terrorists in Sri Lanka, and extremists and fundamentalists in Pakistan and Afghanistan, and in particular with the ISI. He stated that during the current year, i.e., the year 2009, there had already been six bomb blasts in the City of Guwahati at the hands of the ULFA. In the blast which took place on 6th April, 2009 at Malegaon, 9 persons were killed, 62 persons were injured and several vehicles were damaged.

31. SW-8, Mr. Debajit Hazarika, Superintendent of Police, Kamrup District, Assam tendered in evidence his affidavit with all its annexures and stated that the activities of the ULFA were widespread in his State, which

comprised of extortion at gun-point, terrorising the people by bomb blasts and explosions, kidnapping, carrying of illegal arms and ammunitions and attempt to murder. He stated that primarily the ULFA was engaged in waging a war against the State and had active nexus with fundamentalists and terrorist organisations such as the National Democratic Front of Bodoland (NDFB), Harqat-ul-Mujahideen (HUM) and Harkat-ul-Jihad-al-Islami (HUJI). Clear instances of the illegal and unlawful activities of ULFA in the State were cited by him with his affidavit, as Annexure-1 to Annexure-14. The affidavit of this witness along with all its enclosures was exhibited as Exhibit SW-8/G (Colly.).

32. SW-9, Mr. Jitmal Doley, Superintendent of Police, Nalbari District, Assam stated that the affidavit dated 18th February, 2009 was deposed to by him, the contents whereof were true and correct to his knowledge and that the enclosures thereto, Annexure-1 to Annexure-12 (Colly.), were true copies of the official records of his District, that the said annexures pertained to the incidents in his District in which the ULFA was involved and that the activities of ULFA were well documented in his District and there was strong evidence (including witnesses) to show that it was ULFA which was carrying on all these nefarious activities. The unlawful and illegal activities of ULFA included killing, kidnapping for ransom, extortion and attacks on the security forces of the State, and were in fact in the nature of waging war against the

State, which, and if allowed to continue could have serious consequences. The affidavit of this witness along with all its enclosures was exhibited as Exhibit SW-9/H (Colly.).

33. SW-10. Mr. Imdadul Hussain Bora, Superintendent of Police, Darang District, Assam tendered in evidence his affidavit along with Annexure I to Annexure XIII(A), and deposed that during the last two years, the ULFA had continued to indulge in activities such as extortion demands, possession and use of illegal arms and ammunitions and killing, that the ULFA cadres were listed cadres, and that the activities of ULFA were in the nature of waging war against the State. The said activities were well proved and well documented and it could conclusively be said that they were the handiwork of ULFA. The affidavit of this witness along with all its enclosures was exhibited as Exhibit SW-10/J (Colly.).

34. SW-11. Mr. Take Ringu, Superintendent of Police, Special Branch, PHQ Itanagar, Arunachal Pradesh tendered in evidence his affidavit dated 12th March, 2009 along with its enclosures pertaining to the incidents indulged in by the ULFA militants in the (i) Tirap, (ii) Changlang, (iii) Lohit, (iv) Lower Debang Valley and (v) the East Siang Districts. The affidavit of this witness along with its enclosures was exhibited as Exhibit SW-11/K (Colly.). The witness unequivocally stated that whenever there was any operation by the

ULFA in Assam, the ULFA took shelter in the State of Arunachal Pradesh, where also it had created terror by killing of security forces and other innocent persons and by extortions. The ULFA in fact used the State of Arunachal Pradesh as a corridor for going to Myanmar, where they had their camps. Just prior to the filing of his affidavit on 12th March, 2009, the witness stated, one of the ULFA cadres had surrendered in Changlang District in or around 10th March, 2009 with their arms and ammunitions, which were also surrendered. In the current month also, i.e., in April, 2009, he deposed, inputs had been received that the ULFA was having camps in the Lower Debang Valley District. There were also inputs that they were involved in extortion demands from the members of the business community, especially non-locals, and had links with the National Socialist Council of Nagaland - Khaplang (NSCN-K) and other anti-social organisations.

35. SW-12, Mr. Ajoy Kumar Ojah, Additional Superintendent of Police, Tirap District Khonsa, Arunachal Pradesh tendered in evidence his affidavit along with its annexures as Exhibit SW-12/L (Colly.). He deposed that on 15th August, 2008, the Assam Rifles had apprehended a member of the ULFA outfit, namely, Vimal Gogoi from Kanubari Market of Tirap District and recovered four live ammunitions of AK-47 rifle from his possession. In this connection, case FIR No.8/2008 under Sections 10/13 of Unlawful Activities

Prevention Act, 1967 read with Section 25(1) of the Arms Act had been registered at Police Station Kanubari. He further stated that the ULFA had started making serious inroads into the Tirap District.

36. SW-13, Mr. Raken Padu, Superintendent of Police, East Siang District Pasighat, Arunachal Pradesh deposed that the affidavit dated 27.04.2009 with its supportive documents Annexures-'A' to 'G' was sworn by him. He stated that his territory was being used as a hide-out by ULFA after committing operations in the territory as well as in other areas of Assam. On 06.03.2008, two young men, viz., Shri Ranjit Pait and Shri Jiten Morang of Gadam Tinali Village located on the border of East Siang and Lower Debang Valley District went missing. A search was launched for them in the dense forest, but the duo could not be traced out. The father of Ranjit Pait, Head Constable APP Shri B.Pait then received a telephone call from SS LT Mohan Borah alias Jiten Dutta of ULFA to the effect that his son Ranjit Pait and brother-in-law Jiten Morang had been killed for being army informers and working against the ULFA. Their dead bodies were subsequently found concealed in the jungle of Namsing Village area, which had decomposed by the time they were found. In this connection, case FIR No.39/08 under Sections 364/302/120(B)/201/34 IPC had been registered at Police Station Pasighat. Six persons were rounded up from Duimukh Village allegedly for assisting the criminals. Two more persons

both sympathizers of ULFA were absconding from Duimukh Village since 07.03.2008. Threatening calls were also received by the Police warning them not to arrest anybody from Duimukh Village otherwise there would be conflict between the people of Assam and Arunachal Pradesh. In view of the aforesaid threat perception, patrolling had been intensified in Paglam, Namsing and Duimukh Village areas and a combing operation had also been undertaken. During the combing operation in Duimukh jungle, the police recovered and seized some medicines and two solar plates with batteries. The affidavit of this witness along with all its enclosures was exhibited as Exhibit SW-13/M (Colly.).

37. SW-14, Mr. Kime Aya, Superintendent of Police, Changlang District, Arunachal Pradesh stated that his affidavit dated 27th April, 2009 be read in evidence against the ULFA and that the annexures enclosed with the affidavit were true copies of the official records. He stated that the main activities of ULFA were extortions and killings and that the ULFA had links with local insurgent groups and was using the Changlang District as a corridor for going to Myanmar and from Myanmar back to India. The main persons who were the targets of the ULFA were business persons from whom the ULFA extorted money for the purpose of raising funds. The organization "Oil India Limited" and its officials was another target and the general public was being used as

carriers. Around 10th March, 2009, one of the ULFA cadres had surrendered in the Changlang District with their arms, ammunitions, walkie-talkie, etc. The affidavit of this witness along with all its annexures was exhibited as Exhibit SW-14/N (collectively).

38. SW-15, Mr. Tojo Karga, Superintendent of Police, District Lower Debang Valley, Roing, Arunachal Pradesh stated that affidavit dated 27th April, 2009 was deposed to by him, the contents whereof were true and correct to his knowledge and that Annexure-V (Colly.) comprised of true copies of the official records of District Lower Debang Valley, Roing, Arunachal Pradesh. He deposed that his District was being used as a hide-out by the ULFA cadres after their operations, that the ULFA had links with other banned organizations, including the National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) [NSCN-K]; that there was a public out-cry against the activities of ULFA; and that in fact the harassment and terror caused to the public by the ULFA had resulted in the public organizing a rally, which was to take place on the same day in his District, i.e., on 27th April, 2009. He also deposed that apart from the instances mentioned in the annexures to his affidavit, there had been another instance in the last week of March, 2009 of extortion of a businessman from Rajasthan. Out of fear, the said businessman had to leave his business activities in the State of Arunachal Pradesh and flee from the

State. The affidavit of this witness along with all its enclosures was exhibited as Exhibit SW-15/O (Colly.).

39. SW-16, Mr. Isaac Pertin, Superintendent of Police, Lohit District Tezu, Arunachal Pradesh deposed that the affidavit dated 27th April, 2009 had been sworn by him, the contents of which were true and correct to his knowledge. He further stated that the annexures enclosed with his affidavit were true copies derived from the official records of his District. He also deposed that whenever there was an operation in the State of Assam by the ULFA, his District was being used as a hide-out and that temporary camps were set up by the ULFA for the aforesaid purpose in his District. The main object of the ULFA was to destabilize the country and in order to achieve this object, it had created terror amongst the people by carrying on the nefarious activities of attacking the security forces, and resorting to extortion and killing of innocent persons. The members of the security forces and the members of the business community were being specially targetted. The ULFA, SW-16 stated, had links with other banned organisations, including the National Socialist Council of Nagaland –Khaplang (NSCN-K) which was very active in the State. The affidavit of this witness along with all its enclosures was exhibited as Exhibit SW-16/P (Colly.).

40. No one represented the ULFA during the course of sittings at Shillong

on 26th and 27th April, 2009 nor anyone from the general public participated in the enquiry on the said dates. The Central Government was represented through Mr. Baldev Malik and Mr. Shailendra Sharma, Advocates, the State of Assam through Mr. Avijit Roy, Advocate, the State of Meghalaya through Mr. Ranjan Mukherjee, Advocate and the State of Arunachal Pradesh through Mr. Anil Srivastava, Advocate. The evidence of the five witnesses of the State of Meghalaya, the evidence of six witnesses of the State of Arunachal Pradesh and the evidence of five witnesses of the State of Assam was recorded at Shillong. The respective counsel for the State of Meghalaya as well as the State of Arunachal Pradesh thereafter closed their evidence. A statement was made by the learned counsel for the State of Assam that he had twenty more witnesses to examine, who would be subsequently produced, at Guwahati.

41. The Tribunal accordingly had sittings at Guwahati from 11th to 14th May, 2009 for the purpose of recording the evidence of the remaining witnesses of the State of Assam at Guwahati. SW-17 to SW-36 appeared in the witness box at Guwahati to support the notification declaring the ULFA to be an unlawful association. Here again, no one appeared to rebut the case of the State's witnesses and thus the ULFA remained unrepresented throughout. The witnesses examined at Guwahati were SW -17 to SW-36.

42. SW-17, Mr. Arabinda Kalita, Superintendent of Police, Morigaon

District, Assam in the course of his testimony stated that the affidavit dated 17th February, 2009 along with its Annexures, Exhibit SW-17/Q (Colly.), was deposed to by him. In his said affidavit, he had cited instances of the criminal activities in which the ULFA was involved, which were corroborated by the case diaries. The objective of ULFA, the witness testified, was to secede Assam from India by means of violent activities carried out by its cadres, such as large scale kidnappings, extortions, killings, activities involving dishonour to the national flag, intimidation and recruitment of young persons to its cadres. The ULFA had links with terrorist organizations, such as Kamtapur Liberation Organisation (KLO), Peoples Liberation Army of Manipur (PLA), All Tripura Tiger Force (ATTF), Karbi-Longri North Cachar Hills Liberation Front (KLNLF) and National Democratic Front of Bodoland (NDFB). It also had links with Bangladesh and with Pakistan (ISI).

43. SW-18, Mr. Sri Madan Chetia, Commandant, Commando Batalion, North Guwahati stated in the witness box that the affidavit dated 18th February, 2009 along with the enclosures, Exhibit SW-18/R (Colly.), was deposed to by him. He cited instances in his affidavit of the unlawful and illegal activities of ULFA and stated that the case diaries revealed the involvement of the members of the ULFA in the commission of the aforesaid crimes. The ULFA, he stated, had links with other banned organizations in the

North-East, namely, National Socialist Council of Nagaland – Khaplang Faction (NSCN-K), All Tripura Tiger Force (ATTF) and also had nexus with the ISI, both in West Pakistan and Bangladesh.

44. SW-19, Mr. Sri Rana Bhuyan, Superintendent of Police, Baksa District, Mushalpur (BTAD), Assam tendered in evidence his affidavit along with its enclosures as Exhibit SW-19/S (Colly.). In his aforesaid affidavit, he too cited instances of the unlawful and illegal activities being carried on by the ULFA. He deposed that the ULFA was engaged in bomb explosions in public places, murder, kidnapping, extortion for ransom etc., that it had links with other banned organizations like National Democratic Front of Bodoland (NDFB), Kamtapur Liberation Organisation (KLO), and the National Socialist Council of Nagaland – Isak Muivah Faction (NSCN-IM). Apart from this, the ULFA had active links with Bangladesh and with the ISI.

45. SW-20, Mr. Lachit Baruah, Superintendent of Police, Bongaigaon District, Assam stated in the witness box that his affidavit along with its annexures, collectively marked as Exhibit SW-20/T, was true and correct to his knowledge. He deposed that the ULFA was engaged in anti-social and anti-legal activities, such as kidnappings for ransom, extortions, bomb explosions and killings and its aim was to create fear amongst the people so as to terrify them and thus to carry on its terrorist activities. He too testified that the ULFA

had active links with other banned and terrorist organisations, such as Kamtapur Liberation Organisation (KLO), National Democratic Front of Bodoland (NDFB), the Peoples' Liberation Army of Manipur (PLA), Karbi-Longri North Cachar Hills Liberation Front (KLNLF) and with various fundamentalist groups in the neighbouring countries of Pakistan and Afghanistan.

46. SW-21, Mr. Partha Sarathi Mahanta, Superintendent of Police, Dhubri District, Assam tendered in evidence his affidavit along with its enclosures as Exhibit SW-21/U (Colly.), and deposed about the illegal activities of ULFA, with regard to which instances had also been mentioned by him in his affidavit. He stated that usually the ULFA engineered bomb blasts resulting in loss of human lives and indulged in kidnappings, extortions, killings and, in fact, every activity designed to endanger human life. It had active links with the National Democratic Front of Bodoland (NDFB), Kamtapur Liberation Organisation (KLO), Karbi-Longri North Cachar Hills Liberation Front (KLNLF) and All Tripura Tiger Force (ATTF). Apart from this, it also had links with foreign entities and organizations, and in particular with the ISI in Pakistan and Bangladesh.

47. SW-22, Mr. Deepak Choudhary, Superintendent of Police, Jorhat District, Assam deposed that his affidavit dated 17th February, 2009 was sworn

by him and that his said affidavit along with its enclosures was Exhibit SW-22/V (Colly.). The goal of ULFA, he deposed, was to secede Assam from India by waging war against the State and by violent means, such as bomb blasts, kidnappings for ransom, extortions, killing of innocent persons and in fact, the killing of all those who stand for peace and tranquility. He deposed that in Assam, the ULFA had links with other banned organizations, such as National Socialist Council of Nagaland (Khaplang faction) (NSCN-K), Kamtapur Liberation Organisation (KLO) and All Tripura Tiger Force (ATTF). It also had links with various foreign countries with its main base at Bangladesh. Its cadres were trained with the ISI at Pakistan and Afghanistan.

48. SW-23, Mr. Akhilesh Kumar Singh, Superintendent of Police Goalpara District, Assam tendered in evidence his affidavit dated 17th February, 2009 along with its enclosures as Exhibit SW-23/W (Colly), and testified about the secessionist activities of ULFA, which, he stated, was waging war against the country by indulging in bomb blasts, ethnic killing of Hindi speaking persons, large scale extortions and large scale attacks on security personnel. It had links with the National Democratic Front of Bodoland (NDFB), National Socialist Council of Nagaland (Khaplang faction) (NSCN-K) and the Kamtapur Liberation Organisation (KLO), which were Indian militant outfits. It also had nexus with foreign entities, like the ISI in West Pakistan and Bangladesh.

49. SW-24, Mr. Devoiyoti Mukherjee, Superintendent of Police, Barpeta District, Assam tendered in evidence his affidavit along with its enclosures as Exhibit SW-24/X (Colly.) and testified about the secessionist and criminal activities of ULFA, regarding which specific instances were cited by him in his affidavit. He corroborated the version of the earlier witnesses that the ULFA had links with other banned militant organisations as well as with the ISI, and with foreign countries, such as Afghanistan, West Pakistan and Bangladesh.

50. SW-25, Mr. Anurag Agarwal, Superintendent of Police, Special Branch (G), testified that his affidavit dated 18th February, 2009 was sworn by him and the enclosures with the affidavit were true copies of the documents derived from the official records of the District (collectively marked as Exhibit SW-25/Y). The same depicted the various instances of the unlawful activities in which the ULFA was involved, such as bomb blasts, mass killing of innocent persons, extortion, criminal intimidation and ethnic killing of Hindi speaking persons. The ULFA, he deposed, had links with the National Democratic Front of Bodoland (NDFB), Kamtapur Liberation Organisation (KLO), National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) (NSCN-K) and All Tripura Tiger Force (ATTF), which were all banned militant organizations in India. It also had links with foreign militant organizations, such as the ISI, and its cadres were trained in Bangladesh, West Pakistan and Afghanistan.

51. SW-26, Mr. Anand Prakash Tiwari, Superintendent of Police, Udalguri

District, Assam next appeared in the witness box to tender in evidence his affidavit along with its enclosures as Exhibit SW-26/Z (Colly.), and to state that the instances cited in his affidavit about the illegal activities of ULFA were true and correct to his knowledge and the enclosures with his affidavit were derived from the official records of the District. The goal and motto of ULFA, he deposed, was to make Assam a separate and sovereign State by all kinds of insurgent activities. He cited the instance of the Headman of the Village Bhagatpara, who was shot dead recently by the ULFA cadres. The ULFA, he stated, had links with other banned organizations, such as National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) (NSCN-K) and National Democratic Front of Bodoland (NDFB) and the Maoists from Jharkhand, apart from having links with the ISI in West Pakistan and Bangladesh. The ULFA cadres were trained in Pakistan, Afghanistan and Nepal to carry on its nefarious activities.

52. SW-27, Mr. Krishna Kumar Sharma, Superintendent of Police, Karbi Anglong, Assam deposed to the veracity of his affidavit dated 18th February, 2009 and its enclosures, citing instances of the involvement of ULFA in unlawful and illegal activities [Exhibit SW-27/AA (Colly.)]. Significantly, he deposed that the top hierarchy of the ULFA ranks was stationed at Bangladesh and had links with the ISI in Bangladesh as well as in West Pakistan. The

ULFA cadres were also being trained in Bangladesh and West Pakistan. In India, the ULFA had links with other banned militant organizations, such as the National Democratic Front of Bodoland (NDFB) and the National Socialist Council of Nagaland – Isak Muivah (NSCN-IM). From their interrogation reports, it was more than evident that the ULFA was engaged in secessionist activities detrimental to the peace and security of the State of Assam.

53. SW-28, Mr. Surendra Kumar, Superintendent of Police, Sonitpur, Assam deposed that his affidavit dated 18th February, 2009 along with its annexures collectively marked as Exhibit SW-28/BB was true and correct to his knowledge. He testified that he had cited certain cases in his affidavit with regard to the activities of ULFA, which clearly proved the fact that the ULFA was engaged in creating an independent secessionist State through armed struggle and terrorist activities. The ULFA had links with the National Democratic Front of Bodoland (NDFB), the National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) (NSCN-K), Kamtapur Liberation Organisation (KLO) and other banned militant organizations, and more particularly with the ISI in West Pakistan, Bangladesh and Afghanistan.

54. SW-29, Mr. Shyamal Prasad Saikia, Superintendent of Police, Sivasagar District, Assam deposed to the veracity of his affidavit, which, along with the annexures was collectively marked as Exhibit SW-29/CC. He testified that in

his District, the ULFA was engaged in large scale extortion and killing of non-Assamese persons, in particular Hindi speaking persons and persons who hail from outside the State. He further testified that he had cited, as instances, some of the cases which bear out the fact that ULFA was involved in illegal and unlawful activities within his District. For instance, on 16th February, 2008, arms and ammunitions had been recovered from the ULFA in an operation which was conducted by him and which conclusively showed the involvement of ULFA extremists in subversive and unlawful activities against the country. Four of the five ULFA cadres had been killed while one had managed to escape during the course of the encounter. In another operation on 10th June, 2008, the Police from his District and the Army had been forced to open fire and one ULFA militant had got killed while one of his associates, namely, Aditya Naidu @ Tarun @ Karma Panday was apprehended by the Army personnel. On 15th June, 2008, on the basis of credible information, yet another operation was conducted against the ULFA militants, resulting in killing of certain persons from the ULFA cadres and recovery of arms and ammunitions. The witness also corroborated that the ULFA which was waging war against the State of Assam and the Union of India had links with the National Socialist Council of Nagaland (NSCN), Karbi-Longri North Cachar Hills Liberation Front (KLNLF) and National Democratic Front of Bodoland

(NDFB) as well as with ISI in West Pakistan and Bangladesh.

55. SW-30, Mr. Satyaraj Hazarika, Superintendent of Police, Dhemaji, Assam appeared in the witness box to tender in evidence the affidavit of Shri K.J. Saikia, the erstwhile Superintendent of Police of Dhemaji District, who was unable to appear in the witness box for medical reasons. The said affidavit along with its annexures was exhibited as Exhibit SW-30/DD (Colly.), on which the witness identified the signatures of Shri Kangkan Jyoti Saikia on each and every page of the affidavit. The witness stated that the two cases cited in the affidavit with regard to the incidents which took place on 30th May, 2007 and 3rd April, 2008 proved substantially the involvement of ULFA in subversive and illegal activities, though the same were by way of illustration only, as there were several other cases pending against the ULFA and their involvement was well known and well established. The ULFA, he testified, was working very closely with the ISI apart from other banned organisations in India such as National Democratic Front of Bodoland (NDFB), National Socialist Council of Nagaland (NSCN) and Kamtapur Liberation Organisation (KLO), and had camps in Afghanistan, West Pakistan, Bangladesh and Myanmar.

56. SW-31, Mr. A. Deka, Superintendent of Police, Chirang District, Assam deposed to the veracity of his affidavit with its annexures collectively marked

as SW-31/EE. He testified about the aims and objectives of the ULFA being to secede from the Union of India through violent means and by indulging in kidnapping, killing of innocent persons, bomb blasts and the like. The cases cited by him in his affidavit, he stated, clearly established the involvement of ULFA in subversive activities in his State. The said cases, he underlined, were illustrative and not exhaustive as there were innumerable cases against the ULFA in his District. The ULFA had links with the Kamtapur Liberation Organisation (KLO), the National Socialist Council of Nagaland (NSCN), the National Democratic Front of Bodoland (NDFB) and a deep nexus with Bangladesh and with the ISI of West Pakistan.

57. SW-32, Mr. Sayed Ataul Karim, Superintendent of Police, Lakhimpur District, Assam appeared in the witness box to tender in evidence his affidavit along with its Annexures marked as Exhibit SW-32/FF (Colly.) and to testify that the ULFA was a secessionist extremist organization involved in waging war against the Government of India and indulging in killing of innocent persons, particularly Hindi speaking persons, members of the business classes, security personnel and members of the minority community. He stated that he had cited by way of illustration three cases in his affidavit to bear out the involvement of the ULFA in secessionist activities. Raja Baruah, who was arrested in one of the said cases, was an ULFA extremist and his recorded

statement admitting the said fact had been enclosed by him along with his affidavit. He further stated that on 07.04.2008, at about 4.30 a.m. i.e. on the Raising Day of ULFA, an ULFA flag bearing the ULFA symbol (half rising sun in the middle) was found hoisted by the Police of his District at Kalabari Tiniali under Ghilamara Police Station by ULFA activists to show their motto of criminal conspiracy to wage war against the Government of India and to secede Assam from the Union of India. The said flag was seized by a seizure memo, which was enclosed by him with his affidavit. The witness further testified that the ULFA had nexus with other banned militant organizations in India and abroad, such as the National Democratic Front of Bodoland (NDFB), Kamtapur Liberation Organisation (KLO) and Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). It had links with foreign countries, namely, Bangladesh, Bhutan, West Pakistan and Myanmar, where its cadres received training and took shelter. It also had nexus with the Maoists in Nepal and Jaish-e-Mohammed in West Pakistan, which was supported by the ISI.

58. SW-33, Mr. Nitul Gogoi, Superintendent of Police, Nagaon District, Assam deposed to the veracity of his affidavit dated 18th February, 2009, along with its sixteen Annexures, as Exhibit SW-33/GG (Colly.). He testified that his affidavit may be treated as evidence against the ULFA, whose principal aim was to secede Assam from the Union of India by creating terror amongst

the peace loving people and by indulging in bomb blasts, kidnappings for ransom, murder and criminal intimidation of Government servants and business class persons and, in fact, all those who do not support their ideology. He stated that he had cited in his affidavit four cases which clearly showed the involvement of ULFA, but the said cases were illustrative only and not exhaustive. The ULFA had active links with the National Socialist Council of Nagaland (NSCN), Kamtapur Liberation Organisation (KLO) and National Democratic Front of Bodoland (NDFB) in India and with the ISI in Pakistan. Their camps were situate in Bangladesh and they received training in Afghanistan and West Pakistan.

59. SW-34, Ms. Banya Gogoi, Superintendent of Police, Special Operation Unit (SOU), Assam, Dispur, Guwahati tendered in evidence her affidavit as Exhibit SW-34/HH (Colly.), and stated that the contents of the affidavit and those of the annexures enclosed with the affidavit of Mr. S.K. Roy, Joint Secretary, Home and Political Department, Government of Assam (SW-6) were true and correct. In her testimony, this witness delineated the role of the Special Branch in curbing the activities of ULFA by collecting intelligence inputs from all the Districts and also from their own channels and sources. She stated that all the District Superintendents of Police reported to their branch with regard to the information received by them about the activities of ULFA.

and that whenever the Special Branch acquired intelligence inputs with regard to ULFA activities, it disseminated the information to the Districts for necessary action against ULFA and also communicated the information to the higher authorities, i.e., the Police Headquarters and the Government of Assam. The witness further stated that the aim and objective of ULFA was to liberate Assam by waging war against the country and by armed struggle against the Government of India. The ULFA was running training camps in Upper Myanmar as well as in Sherpur District in Bangladesh. In 2008, the witness stated, as set out in her affidavit, the ULFA had observed its Raising Day and Army Day in the training camp of Sherpur District of Bangladesh and in the flat of Mr. Paresh Baruah in Dhaka, as per information derived from two surrendered ULFA cadres, whose statements were annexed with the affidavit of SW-6, Mr. S.K. Roy. The witness further stated that the ULFA was still continuing its recruitment drive and had recruited a large number of youth from different parts of the State, who were being imparted training by foreign agencies such as ISI in Pakistan and DGFI of Bangladesh. This training was imparted with a view to train ULFA in carrying out terrorist activities. The witness also highlighted the link between the ULFA and the Islamic militants, who had together chalked out a plan to hijack an aircraft from Guwahati. The statements of ULFA cadres were recorded in this context and formed part and

parcel of the affidavit of SW-6, Mr. S.K. Roy. The witness further deposed that the ULFA had been regularly asking the people of Assam to boycott the observance of Republic Day and Independence Day and to observe general strike on these two specific days in the State. The paper clippings of publications in local dailies in this regard had also been enclosed with the affidavit of SW-6, Mr. S.K. Roy along with the detailed chart showing the involvement of ULFA in murderous attacks, bomb blasts, kidnappings, extortions, large scale destruction of public and private property and serial killings. The mouth-piece of ULFA, the witness stated, was "FREEDOM". The contents of this publication related to waging war against the State and publication of articles in order to boost the morale of the ULFA cadres. Viewed comprehensively, according to the witness, these activities were designed by the ULFA to wage war against the Government of India and to strike at the sovereignty of the Nation, and included targeting of the national resources of the country, such as the Oil Sector, the Surface Transport and the Communication Network. In the last three or four years, their emphasis had been on large scale killings of innocent persons by explosions, by targeting busy thoroughfares, crowded market places and business centres, as their aim was to attract limelight.

60. SW-34, Ms. Banya Gogoi also deposed about the two recent instances

of bomb blasts in Guwahati city which took place on 31st March, 2009 and 6th April, 2009, the links of ULFA with All Tripura Tiger Force (ATTF), National Democratic Front of Bodoland (NDFB), People's Liberation Army of Manipur (PLA), National Socialist Council of Nagaland (Khaplang faction) (NSCN-K) and Kamtapur Liberation Organisation (KLO). The latter, she stated, was active in the North Bengal corridor of West Bengal. The ISI of Pakistan and the DGFI of Bangladesh, the witness further stated, was also actively supporting the ULFA and its activities. The Chief of Staff of ULFA and its Central Executive Committee members were already there in Bangladesh and the Government of Assam had positive information to the effect that the erstwhile Government of Bangladesh had been actively and logistically supporting the ULFA cadres. The instructions for the activities of ULFA, according to the witness, came from the top hierarchy in Bangladesh and were implemented in the State of Assam by the middle level and the lower middle level cadres. The very fact that the ULFA cadres had taken refuge in foreign countries showed that the ULFA was being actively supported by countries such as Bangladesh and Pakistan, otherwise they could not have sustained in the said countries.

61. SW-34, Ms. Banya Gogoi also tendered in evidence an additional affidavit dated 14th May, 2009 with regard to the publication in the English

and vernacular newspapers, the broadcasting and telecasting and affixation of notices with regard to the sittings of the Tribunal held in Guwahati on the 11th, 12th, 13th and 14th May, 2009. The said affidavit was marked as Exhibit SW-34/JJ (Colly.).

62. SW-35, Mr. Diganta Barah, Superintendent of Police, Tinsukia District, Assam next appeared in the witness box to depose about the veracity of his affidavit, which, along with its Annexures was exhibited as Exhibit SW-35/KK (Colly.). The aim and objective of ULFA, the witness stated, was to wage war against the Government of India demanding the secession of Assam from the Union of India through violent means. In his District, he stated, the ULFA was extremely active and was involved in large scale kidnapping, extortion and killing of innocent persons, thereby creating a fear psychosis among the general public. The witness also testified about the bomb explosions in his District and that the statements of witnesses unequivocally established that the said bomb explosions were the handiwork of ULFA. He deposed about the active links of ULFA with other banned militant organizations in India, such as Kamtapur Liberation Organisation (KLO), National Socialist Council of Nagaland (NSCN) and National Democratic Front of Bodoland (NDFB) as well as its links with the ISI in West Pakistan and in Bangladesh and also with militant organisations in Afghanistan. He cited instances in his affidavit and

testimony regarding the activities of hard core militants in the ULFA cadres.

63. SW-36, Mr. Bir Bikram Gogoi, Additional Superintendent of Police (Head Quarter), Golaghat District, Assam tendered in evidence his affidavit dated 19th February, 2009 along with its enclosures as Exhibit SW-36 L1 (Colly.), and deposed that the aim and objective of ULFA was to secede Assam from the country. The witness also deposed about the nature of offences committed by the ULFA in his District, such as extortion, murder, kidnapping and sabotage by use of explosives. He stated that he had presented six cases in his affidavit which established that the ULFA was engaged in waging war against the State, but the said cases were illustrative and not exhaustive. He also testified that the killings, extortions and bomb explosions were continuing unabated. The ULFA, he stated, had active links with banned militant organizations in the country, such as both factions of the National Socialist Council of Nagaland (NSCN) and with the National Democratic Front of Bodoland (NDFB) and also with certain organizations which were not banned, such as Karbi-Longri North Cachar Hills Liberation Front (KLNLF). The witness stated that they had definitive evidence from revelations made by various ULFA cadres after their arrest as well as from other sources that the ULFA had active links with foreign entities and organisations, such as the Pakistan Inter-Service Intelligence (ISI) and other Jehadi organizations like

HUJI, etc. based in West Pakistan and in Bangladesh.

64. SW-37, Mr. R.R. Jha, Director to the Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi appeared in the witness box to tender in evidence his affidavit along with its Annexures, which affidavit, he stated, bore his signatures. He deposed that the affidavit and the Annexures, exhibited as Exhibit SW-37/MM (Colly.), may be read as part of his evidence. He also testified that even after the filing of his affidavit on 24th February, 2009, the ULFA was continuing with its unlawful and illegal activities in the States of Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Nagaland. The details of the major incidents committed by the ULFA during the years 2006, 2007 and 2008 were delineated in his affidavit and in Annexure-III thereto, including incidents of explosion, attacks on Hindi speaking persons, encounters with security forces, attacks/kidnappings of civilians, incidents of extortion, incidents of arson, hoisting of the flag of the ULFA on the occasion of ULFA's Raising Day on 7th April, 2008, snatching of the national flag by two ULFA cadres on August 15, 2008, incidents of blasts on August 15, 2008 (Independence Day). Also delineated were particulars of the ULFA's extortion drive, its recruitment and training in foreign soil, training of handling explosives, nexus with Jihadis and the ISI, nexus with foreign intelligence agencies, such as the DGFI (Directorate General of Forces Intelligence) and BDR of Bangladesh and the

2241 GJ 09-12

establishing of a new camp by the ULFA in Bhutan in the wake of the operations by the Royal Bhutan Army, and ULFA's boycott call of the Republic Day and the Independence Day.

65. After the recording of the statement of SW-37 Shri R.R. Jha, Shri Baldev Malik, Advocate closed the evidence of the Union of India. Thus, in all, five witnesses were examined by the State of Meghalaya, six witnesses by the State of Arunachal Pradesh, twenty-five witnesses by the State of Assam and one witness on behalf of the Central Government, who tendered on behalf of the Central Government a substantial affidavit by way of evidence. All the aforesaid witnesses were available for cross-examination with the relevant records, but despite service of notice on the ULFA and the widespread publicity given to the sittings of the Tribunal at Shillong, Guwahati and New Delhi, there was no representation from the ULFA, at any juncture. Then again, despite opportunity given, no one from the public appeared to tender any affidavit or evidence whatsoever.

66. The case was listed for arguments on 19th May, 2009, on which date submissions were made on behalf of the Union of India and the States of Assam, Meghalaya and Arunachal Pradesh. Again, there was no representation on behalf of the ULFA nor any person from the general public appeared before the Tribunal.

67. An analysis of the evidence on record establishes that the ideology of the ULFA, which association came into existence on April 07, 1979 at the historic Rongghar Maidan in Sivasagar District following the teachings of : Marzism and Mao-Leninism, was to establish an independent and sovereign country in Assam. The means adopted was an armed struggle, the ULFA avowedly being a revolutionary political group. To achieve this end, the ULFA adopted its own flag and emblem and provided for its own infrastructure, including its own Central Executive Assembly and Judiciary Department. The constitution of the ULFA even provided for the appointment of a Foreign Secretary and the Chief of the Army.

68. The evidence further establishes that the ULFA to achieve its objective is active in varying degrees all over the Brahmaputra Valley, including the States of Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Nagaland. Recently, it appears to have increased its activities in the East and West Garo Hills of Meghalaya, which the outfit routinely uses for transportation of weapons and explosive materials. In Arunachal Pradesh, it has shown its presence in the Lohit, Changlang and Tirap Districts, which the outfit uses for infiltration from or exfiltration to Myanmar, where the base camps of the 28 Battalion of the outfit are located. Charts of the details of major incidents committed by the ULFA particularly during the years 2006, 2007 and 2008 and the areas where

they were committed have been deposed to by a number of witnesses,

including SW-6, Shri S.K. Roy, Joint Secretary, Home and Political

Department, Assam Sachivalaya, Dispur, Guwahati and SW-37, Mr. R.R. Jha,

Director to the Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi

69. The witnesses in one voice have deposed about the coercive methods used by the ULFA including bomb explosions, murderous attacks and extortions, and the general atmosphere of terror created by this outfit, compelling most of the victims of extortion to pay to the outfit huge sums of money even without informing the Police. The ULFA's widespread extortions, it is on record, have yielded the outfit crores of rupees, which are being utilised for financing its organisational machinery, training programmes and arms procurement drive.

70. It is evidence that the outfit was initially declared an 'unlawful association' under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 with effect from 27th November, 1990 and thereafter the notification declaring ULFA an 'unlawful association' has been extended from time to time. It also emerges from the record that the criminal activities of ULFA despite the ban having been extended from time to time, continue unabated. As a matter of fact, 560 violent incidents and killing of 346 persons, including 29 members of security forces are attributable to the ULFA during the period from 1st January, 2006 to

15th October, 2008. Recent reports indicate that the ULFA was involved in 9 serial blasts in different Districts of Lower Assam on 30th October, 2008, which resulted in the killing of 76 persons and injuring over 351 persons.

71. A conjoint reading of the affidavits of the witnesses, who have deposed against the unlawful and illegal activities of ULFA, along with their statements made before the Tribunal conclusively establish that the illegal and violent activities of ULFA are intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India in furtherance of its objective of liberation of Assam. For the aforesaid purpose, the ULFA, which, as stated above is a revolutionary political party, has allied itself with other unlawful and banned organisations of the North-Eastern region and even during the subsistence of the ban has engaged in several unlawful and violent activities with a view to secede Assam from India, including a spate of extortions, killings and kidnappings for ransom. That it has established sanctuaries and training camps in neighbouring countries, particularly in Afghanistan, Pakistan and Bangladesh for the open propagation of anti-national activities in collusion with forces inimical to India's sovereignty and national integrity also stands established on record.

72. Recently, as is clear from the evidence of the witnesses, it has mobilised its cadres for escalating its secessionist, subversive and violent activities and is indulging in increased killings of civilians, particularly persons from the

business classes and targeting of Police and Security Forces' personnel. It is also well documented that the ULFA is procuring and inducting more and more illegal arms and ammunitions from across the border, for which purpose it is extorting and collecting huge funds and illegal taxes from the public. The youth of the North-Eastern region are being incited to join its ranks for the furtherance of secessionist activities while the general public is living under a fear psychosis generated by its violent activities.

73. Significantly also, the witnesses in unison have stated that the activities of ULFA are now well documented in view of the fact that they are reported to the Special Branch and the Police Headquarters of Assam, which, in turn, communicate the same to the Government of Assam. This has enabled almost all the witnesses to prove on record various FIRs, statements of witnesses, seizure lists, copies of demand letters, extortion notices and statements of accused persons, including interrogation statements, admitting to their criminal activities.

74. The witnesses have further highlighted that the ULFA is maintaining operational links with the Liberation of A'chik Elite Force (LAEF), People's Liberation Front (PLF), National Democratic Front of Bodoland (NDFB), Harqat-ul-Mujahideen (HUM), Harkat-ul-Jihad-al-Islami (HUJI), A'chik National Volunteers Council (ANVC), Kamtapur Liberation Organisation

(KLO), Tripura People's Democratic Front, National Socialist Council of Nagaland (Isak Muivah) (NSCN-IM), National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) (NSCN-K), Karbi-Longri North Cachar Hills Liberation Front (KLNLF), All Tripura Tiger Force (ATTF), Peoples' Liberation Army of Manipur (PLA), Maoists from Jharkhand, ISI in West Pakistan and Bangladesh, DGFI of Bangladesh and Liberation Tigers of Tamil Elam (LTTE), to secede Assam from India. The ULFA cadres are being imparted training by the Pakistani Intelligence Agency, Inter-Services Intelligence (ISI), in addition to being trained by their own experts. Top ULFA leaders are taking shelter in Bangladesh to evade arrest, where also training camps have been set up. It is also on record that some cadres are taking shelter in Bhutan and Myanmar and that the State of Assam is being used as a corridor to various foreign countries. Some Districts in Assam, Meghalaya and Arunachal Pradesh, as set out in the evidence of the witnesses mentioned hereinabove, are being used as hideouts.

75. The evidence led by the Governments of Assam, Meghalaya and Arunachal Pradesh as well as the evidence led by the Union of India has remained un rebutted and unimpeached before this Tribunal in view of the fact that the ULFA has not chosen to adduce any evidence or even to file any representation on its behalf.

76. The continued declaration of the ULFA as unlawful has been prayed for by all the witnesses in one voice as necessary to prevent the outfit from openly indulging in its anti-National activities in collusion with foreign powers inimical to India's security concerns. The witnesses have stated that to curb the activities of ULFA is the crying need of the day, as the tremors of the violence being unleashed by the ULFA are being felt throughout the State and its main targets, viz., the Hindi speaking populace, the Police and security personnel, and the members of the business classes, are feeling the brunt of its activities to the extent of perpetually living under the shadow of fear.

77. In this view of the matter and keeping in mind that the object of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 is to make powers available for dealing with the activities directed against the integrity and sovereignty of India, this Tribunal is of the opinion that the Central Government was fully justified in reaching the conclusion that the ULFA is an 'unlawful association' as defined in the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the activities of ULFA being detrimental to the sovereignty and integrity of India. The further opinion of the Central Government declaring the ULFA along with all its factions, wings and front organisations as unlawful associations *with immediate effect* with a view to curtail its unlawful and violent activities and to prevent remobilisation of its cadres in furtherance of its illegal aims and

objects also appears to be wholly justified, keeping in view the threat perception created by this outfit despite the earlier ban orders. Accordingly, the declaration made by the Government of India by Notification S.O. No.2746(E) dated 27.11.2008, pursuant to the powers exercised under Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 deserves to be confirmed and it is hereby declared and held that the aforesaid Notification is confirmed.

The reference stands answered in the terms mentioned above.



JUSTICE REVA KHETRAPAL

UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL

MAY 22, 2009

km